

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8>> पिरदा की जमीन का अधिग्रहण ...

रायपुर एम्स के मंच से उपराष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ को संदेश

प्रदेश नक्सलवाद खात्मे के बाद विकास के पथ पर : राधाकृष्णन

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की कहानी आज रायपुर एम्स के मंच पर साफ दिखाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तीसरे दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि नए भारत और नए छत्तीसगढ़ के बदलाव का प्रतीक बन चुका है

छात्रों के लिए नई जिम्मेदारियों का संदेश

एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 689 डिग्री प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए, जबकि उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 16 विद्यार्थियों को पुरस्कारों से

सम्मानित किया गया। मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

दीक्षांत समारोह जश्न के साथ बड़ी जिम्मेदारी का पल

छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल सफलता का उत्सव नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों की शुरुआत भी है। उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर का विकास, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में हो रहे बदलाव का प्रतिबिंब है। एडवांस्ड हेल्थकेयर, रिसर्च और अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एम्स रायपुर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य के पहले स्वेप किडनी ट्रांसप्लांट को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

जहां कभी हिंसा थी, वहां आज हो रहा विकास

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की चुनौती पर बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने



कहा कि राज्य अब डर और अभाव के अतीत से निकलकर शांति, तरक्की और अवसरों की ओर बढ़ रहा है। जिन इलाकों में कभी हिंसा का बोलबाला था, वहां आज सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी सुरक्षा उपायों

को अहम बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले लोग इलाज के लिए एम्स तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन अब देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इस तरह हुआ है कि एम्स लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए विस्तार का भी उल्लेख किया और युवाओं से नशीली दवाओं से दूर

रहने की अपील की।

मरीजों के लिए सहानुभूति रखें- अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर

रहा है। उन्होंने अंग प्रत्यारोपण, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया के उन्मुक्तन में संस्थान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने जा रहे युवाओं को एक मजबूत और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही, मरीजों के उपचार में सहानुभूति को भी उतना ही जरूरी बताया और दृढ़ साक्षरता पर जोर दिया।

राज्यपाल ने गोल्डन आवर का बताया महत्व

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि डॉक्टरों का हर फैसला लोगों के जीवन पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। उन्होंने जान बचाने में गोल्डन आवर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एम्स रायपुर की सुविधाओं का लाभ सिर्फ रायपुर और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी मिल रहा है।

उन्होंने तेजी से बदलती स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ चिकित्सा जगत को भी खुद को लगातार अपडेट करने की जरूरत बताई।

देशभर में पहचान बना रहा एम्स रायपुर

समारोह में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, एम्स रायपुर के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉ। संजीव हांडा और एंजीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एम्स रायपुर का तीसरा दीक्षांत समारोह सिर्फ 689 विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता का उत्सव नहीं जाना, बल्कि यह नए छत्तीसगढ़ का बदलती तस्वीर का भी संदेश लेकर आया। नक्सलवाद से विकास तक और इलाज की जरूरत से आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक छत्तीसगढ़ में विकास तेजी से हो रहा है।

शुद्धिकरण विवाद इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी रैली के बाद हुए शुद्धिकरण विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बुधवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि संघ ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक छुआछूत को पाप और धर्म के खिलाफ माना है।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि आरएसएस का स्पष्ट मत रहा है कि छुआछूत गलत है और इसे धर्म के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण' विवाद को लेकर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस



कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी ने इस रस्म को छुआछूत का दूसरा नाम बताया था और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन

कांग्रेस संविधान विरोधी, छुआछूत को आरएसएस ने पाप माना

किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मनुस्मृति भी जलाई। मनुस्मृति जलाने के सवाल पर इंद्रेश कुमार ने कहा कांग्रेस के ये सारे आरोप और विरोध इसलिए हैं क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी है जिसमें छुआछूत है और यह संविधान के खिलाफ है, कांग्रेस खुद इन सारे आरोपों का सामना कर रही है। इसलिए, खुद को साफ दिखाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से दूसरा ईसान गंदा नहीं हो जाता। कहा जाता है कि अगर आप चांद या सूरज पर थूकते हैं, तो वह आपके ही चेहरे पर गिरता है। इसलिए, ये सारे आरोप और उनका चीजों को जलाना सिर्फ यही साबित करता है कि वे दिन-ब-दिन अपनी नैतिकता खो रहे हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने 31 बंगलादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से 31 बंगलादेशी नागरिकों को अपनी हिरासत में लिया और मंगलवार देर रात उन्हें मालदा के इंग्लिश बाजार में बने एक अस्थायी हिरासत केन्द्र में भेज दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समूह कल रात करीब 11:30 बजे ट्रेन से मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचा और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान उन्हें बस से हिरासत केन्द्र ले गए। सूत्रों के मुताबिक इन बंगलादेशी नागरिकों ने कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था और वे बेंगलुरु में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे थे। भारत में रहने के लिए जरूरी वैध कागजात न होने के कारण कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। खबरों के अनुसार इन 31 लोगों को बेंगलुरु शहर के कम से कम आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिया गया था। इस समूह पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हैं; मालदा लाए गए लोगों में कुछ परिवार भी हैं। अधिकारियों ने अभी तक इनके वापस भेजने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बंगलादेश वापस भेजने की औपचारिक प्रक्रिया से पहले उनकी पहचान और नागरिकता की पुष्टि की जाएगी।

पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र बने राम मंदिर के सीईओ

गोविंददेव गिरि को महासचिव का दायित्व

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को अयोध्या में संपन्न हुई, जिसमें ट्रस्ट के तीन रिक्त पदों पर नये न्यासियों की नियुक्ति के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के चयन को मंजूरी दी गयी। चयन समिति की अनुरोधों के बाद सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सीईओ के चयन के लिए गठित समिति के समक्ष करीब पांच हजार आवेदन आये थे। आवेदनों की जांच और साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद समिति ने तीन नाम तय किये थे। ट्रस्ट की बैठक में विचार-विमर्श के बाद श्री मिश्र को मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। देवरिया निवासी जितेंद्र मिश्र भारतीय वायुसेना में करीब 39 वर्ष तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। सैन्य एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गयी है। उन्हें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पश्चिमी कमान का नेतृत्व कर चुके हैं।



प्रमुख समाचार

विदेश मंत्री आज से यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर गुरुवार से यूक्रेन और पोलैंड की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। जयशंकर को यूक्रेन यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब कोव और मॉस्को के बीच जारी संघर्ष में तनाव और शत्रुता और बढ़ गई है। ऐसे में उनकी यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया, “विदेश मंत्री एस. जयशंकर तीन से पांच सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे।” मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान जयशंकर अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही, यह क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर भी प्रदान करेगी।

नासिक में राहुल के दौरे पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

मुंबई। नासिक की महापौर हिमगौरी आहेर-अडके, भारतीय जनता पार्टी की अन्य महिला नेताओं और समर्थकों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नासिक दौरे के विरोध में बुधवार को मार्च निकाला और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विरोध कर रही है। भाजपा महिला मोर्चे की कई कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुईं और उन्होंने गांधी के खिलाफ “वापस जाओ” के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर महिला सशोकीकरण का विरोध करने का आरोप लगाया। भाजपा समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि गांधी छात्रों के प्रदर्शनों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि राहुल महिला आरक्षण विधेयक का सम्मान करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को नासिक के दौरे पर हैं, जहां वह पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन अभियान में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।



पाकिस्तान ने मोदी की फोटो क्रांप की तो भड़क गये शिंदे

मुंबई। पाकिस्तान की ओर से की गयी ‘तस्वीरबाजी’ पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भड़क उठे हैं। शिंदे सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को क्रांप किए जाने को लेकर शिंदे ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ इस तरह के खेल खेलने की कोशिश न करे। शिंदे ने तीखे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ने भले ही तस्वीर से मोदी को हटा दिया हो, लेकिन अगर मोदी चाहें तो पाकिस्तान को ही दुनिया की तस्वीर से हटा सकते हैं। दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से एससीओ सम्मेलन की फैमिली फोटो का एक संपादित संस्करण साझा किया गया, जिसमें शरीफ को केंद्र में दिखाया गया और कई नेताओं को तस्वीर से बाहर कर दिया गया। मूल तस्वीर 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन के एक सत्र से पहले ली गई थी।



एआईएमआईएम छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए आसिम वकार

लखनऊ। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पूर्व नेता आसिम वकार 2 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वकार ने एआईएमआईएम की आलोचना करते हुए कहा कि हालांकि पार्टी ऊपरी नेतृत्व के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती दिखती थी, लेकिन असल में उसका मुकाबला कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से था। वकार ने कहा कि भारत में देश से प्यार करने वाले सभी लोगों का मकसद भाजपा को सत्ता से हटाना और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह तरीका मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। वकार ने बंगाल के नेता हुमायूं कबीर का भी जिक्र किया, जिन पर उन्होंने बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कबीर को 1,100 करोड़ रुपये मिले थे।



जीडीपी पर सियासत : मोदी सरकार पर विपक्ष का तीखा वार

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सरकार द्वारा इन आर्थिक आंकड़ों का जश्न मनाने और शेयर बाजार में आई भारी गिरावट की तुलना की। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, शेयर बाजार में खुशी की लहर... 7.8% जीडीपी ग्रोथ ने पूरे देश में जश्न और भरोसे का ऐसा माहौल बना दिया है कि...संसेक्स 788 अंक गिर गया। खेड़ा का यह तंज तब आया जब बुधवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इंडेक्स पर भारी बिकवाली का दबाव देखा गया; संसेक्स करीब 788 अंक गिर गया और निफ्टी 23,850 के स्तर से नीचे खुला। बाजार में यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर पर रहने के बीच आई, जिससे निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ। कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी भारत के हालातिया जीडीपी आंकड़ों के महत्व को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक बहस के बीच आई है, जिसमें सरकार पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के सबूत के तौर पर पेश कर रही है।



भागवत की अमेरिका यात्रा : भारतीय चिंतन की सार्थक प्रस्तुति

तलित गर्ग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की अगस्त 2026 की अमेरिका यात्रा को केवल प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम तक सीमित करके देखा उसके व्यापक अर्थ को छोटा करना होगा। न्यूयार्क में 29 अगस्त को आयोजित ‘एक विश्व, एक मानवता’ कार्यक्रम में उनका संबोधन ऐसे समय हुआ, जब संघ को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक धारणाएं, आरोप और पूर्वाग्रह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे वातावरण में भागवत ने जिस प्रकार विविधता, संवाद, सेवा, सह-अस्तित्व और मानवीय एकात्मता को केंद्र में रखा,

उसने संघ की विचारधारा को उसके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समाज के सामने भी एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके विचार अब भारत की सीमाओं से बाहर भी व्यापक चर्चा का विषय बन रहे हैं।

भागवत का अमेरिका जाना वस्तुतः संघ के विचार को प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से समझाने का अवसर बना। संघ के बारे में भारत में लंबे समय से दो विपरीत धारणाएं दिखाई देती रही हैं। एक पक्ष उनका भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभावना, सेवा और सामाजिक संगठन की विराट शक्ति मानता है, जबकि दूसरा पक्ष उसके विचारों को संकीर्ण धार्मिक

राजनीति से जोड़कर देखता है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने समय-समय पर संघ और उसके विचारों पर गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाए हैं। अमेरिका में भी कार्यक्रम से पहले कुछ संगठनों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भागवत की यात्रा और संघ की विचारधारा पर आपत्तियां व्यक्त कीं। ऐसे माहौल में किसी संस्था का वास्तविक छवि केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बनती, वह संवाद से बनती है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। भागवत ने अपने विचार विरोधियों पर आक्रमण करके नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की व्याख्या करके सामने रखे। इससे संघ को लेकर बनी धारणाओं पर बहस का एक नया आधार तैयार हुआ।



न्यूयार्क में भागवत के वक्तव्य का सबसे अधिक चर्चित पक्ष उनका हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर स्पष्ट कथन रहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। यह कथन राजनीतिक नारे से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हिंदुत्व की उनकी व्याख्या को सामाजिक समावेश के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित

किया कि सत्य एक है और उसे समझने तथा व्यक्त करने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह मतभिन्नता को ही अस्तित्व के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में देखने की क्षमता रखती है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है-यदि हिंदुत्व का अर्थ भारत की सांस्कृतिक चेतना है, तो क्या वह किसी समुदाय को भारत से बाहर कर सकता है? भागवत का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखाई देता है। उनका कथन हिंदुत्व की उस व्याख्या को सामने रखता है, जिसमें भारतीयता किसी एक पूजा-पद्धति की बपौती नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत है।

भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित हैं। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है। यह संदेश आज के विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अनेक देशों में धार्मिक विवाद, नस्लीय भेद, सांस्कृतिक असहमति और राजनीतिक ध्ववीकरण सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय भारत का अनुभव यह बताता है कि भिन्नताओं को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें सम्मान देकर भी एकता स्थापित की जा सकती है। यही विचार भागवत

के संबोधन को सामान्य राजनीतिक भाषण से ऊपर उठाता है। उनका अग्रह था कि विविधता को स्वीकार ही नहीं, सम्मान और संरक्षण भी मिलना चाहिए। संघ की सांस्कृतिक अखंडता के रूप में प्रस्तुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक विमर्श से निर्मित हुआ है, जबकि संघ स्वयं को सामाजिक संगठन और सेवा-आधारित सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। यही वह बिंदु है जहां संघ की छवि को केवल चुनावी राजनीति के चश्मे से देखने की सीमा सामने आती है। किसी संगठन को समझने के लिए उसके राजनीतिक प्रभाव के साथ उसकी सामाजिक गतिविधियों, सेवा-कार्य, संगठनात्मक संस्कृति और वैचारिक आधार को भी देखना आवश्यक है।

शांति • संस्कृति • विकास • निवेश • समृद्धि

विकास भी, विश्वास भी

बस्तर : विकास, विश्वास और समृद्धि की नई गाथा

शांति, पर्यटन, उद्योग और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर बदलती तस्वीर

कभी नक्सली हिंसा और पिछड़ेपन की पहचान रखने वाला बस्तर आज विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की भूमि के रूप में उभर रहा है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों, सुरक्षा के सुदृढ़ प्रयासों और जनभागीदारी से यहां शांति स्थापित हुई है और उद्योग, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026 का बस्तर नई ऊर्जा, नए अवसर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है।

“ नया बस्तर, नए भारत के विकास संकल्प का सशक्त प्रतीक है।
-नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

“ विकास की मुख्यधारा से जुड़ता हर गांव, हर परिवार।
-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



शांति की मजबूत नींव पर विकास

सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से बस्तर अब तेजी से शांति और विश्वास की ओर बढ़ रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क, पुल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल पहुंच रहे हैं।

हजारों परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। गांव-गांव में विकास की रोशनी फैल रही है और लोग मुख्यधारा से जुड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हैं।



ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से बदलती तस्वीर



पर्यटन से खुल रहे अवसरों के द्वार

चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और प्राकृतिक धरोहरें बस्तर की पहचान हैं। सरकार पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने हेतु ईको-टूरिज्म, होम स्टे, सांस्कृतिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट के विकास पर लगातार कार्य कर रही है।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदायों को हजारों रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।



चित्रकोट जलप्रपात बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य



उद्योग, निवेश और नई संभावनाएं

नई औद्योगिक नीति से बस्तर निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, वनोपज, हस्तशिल्प, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

स्थानीय युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिल रहा है जिससे रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।



उद्योगों से बढ़ते रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर कदम



जनजातीय संस्कृति से वैश्विक पहचान तक

बस्तर की जनजातीय कला, शिल्प, लोकनृत्य और परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। सरकार इन पारंपरिक कलाओं को आधुनिक बाजार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इससे शिल्पकारों की आय बढ़ रही है और बस्तर की संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।



ढोकरा कला - बस्तर की विशिष्ट पहचान



बस्तर दशहरा - विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव



महिला स्व-सहायता समूह सशक्त होते आत्मनिर्भर परिवार



कृषि और सिंचाई से बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण संरचनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों से किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा मिल रही है। कृषि के साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वनोपज आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ रही है और गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।



जनकल्याण से सशक्त होता बस्तर

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से हजारों परिवारों का जीवन बेहतर हो रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, युवाओं को कौशल और रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण तथा बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिलने से बस्तर का हर परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है।



शांति से समृद्धि की ओर बढ़ता बस्तर, आत्मविश्वास, अवसर और नई पहचान का प्रतीक है।

विकसित बस्तर : विकसित छत्तीसगढ़ : विकसित भारत

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का विमानतल पर किया आत्मीय स्वागत

रायपुर। उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन के



छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया। उपराष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में ख़ाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयालदास बबलर, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा, राज्य सभा सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने आत्मीय स्वागत की। इसी प्रकार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री सुनील सोनी, श्री मोती लाल साहू और जनप्रतिनिधि श्री अशोक बजाज और मुख्य सचिव श्री विकासशील, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में आत्मीय स्वागत किया।

शिक्षक दिवस पर 68 शिक्षक होंगे सम्मानित

वार शिक्षकों को मिलेगा स्मृति पुरस्कार

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को प्रदेश के 68 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य के लिए चार शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। सम्मान समारोह शनिवार को सुबह 11 बजे लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में होगा। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री गर्जेंद्र यादव की मौजूदगी में शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षकों में प्राचार्य, प्रधान पाठक, व्याख्याता और सहायक शिक्षक सहित शिक्षा विभाग की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। स्मृति पुरस्कार के लिए खेरागढ़ के राजेश, कोरबा के कामता, दुर्ग की प्रज्ञा सिंह और सारांगढ़ की प्रियंका का चयन किया गया है।

खम्हारडीह, उरला, गुढ़ियारी और खमतराई पुलिस ने 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार

रायपुर। खम्हारडीह, उरला, पंडरी, गुढ़ियारी और खमतराई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया जिसमें एक आरोपी को धारदार हथियार के साथ तो एक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया जबकि 8 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे के नेतृत्व में की गई। गुढ़ियारी पुलिस ने शुक्रवारी बाजार निवासी जुगनु साहू उर्फ गोल्डू (35) को धारदार हथियार के साथ पकड़ा। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 382/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई। उरला पुलिस ने राजू भारती (47), निवासी अटल आवास उरला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 417/2026, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। खम्हारडीह पुलिस ने 4 बदमाशों पर धारा 170/126, 135 (3) बीएनएसएफ के तहत कार्रवाई की, पंडरी पुलिस 2 बदमाशों पर धारा 170, खमतराई पुलिस ने 2 बदमाशों पर धारा 170 के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया।

दूपमरे ने अगस्त माह में विशेष टिकट जांच अभियान से वसूले 4.19 करोड़

रायपुर/ बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे



द्वारा यात्रियों को सुगम एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने, रेलवे नियमों के पालन को सुनिश्चित करने तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अगस्त माह में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडलों बिलासपुर, रायपुर एवं नागपूर में ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में सघन एवं प्रभावी टिकट जांच की गई। अभियान के दौरान कुल 60,822 अनियमित एवं बिना टिकट यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा उनसे 4,19,31,888 का जुर्माना वसूल किया गया। विशेष टिकट जांच अभियान के माध्यम से यात्रियों को उचित एवं वैध टिकट लेकर यात्रा करने तथा रेलवे के निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही, बिना उचित टिकट के अधिक लगेज लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार लगेज बुक कराने के लिए प्रेरित किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे हमेशा वैध एवं उचित टिकट के साथ ही यात्रा करें तथा निर्धारित सीमा से अधिक लगेज होने पर उसकी नियमानुसार बुकिंग कराएं।

राजधानी/छत्तीसगढ़

विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति का योगदान सर्वोपरि : रूपकुमारी

■तीन करोड़ लखपति दीदीयों और देश की आर्थिक प्रगति का किया उल्लेख

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएँ सशक्त और आत्मनिर्भर होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद रूपकुमारी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित केन्द्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार मानते हुए कहा कि स्वर्गीय करुणा शुक्ला और डॉ. सरोज पाण्डेय के बाद संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी, भाजपा

प्रदेश प्रवक्ता द्वय शताब्दी पाण्डे व डॉ. किरण बघेल, और महिला मोर्चा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष कृतिका जैन उपस्थित रहीं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिला शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। आज महिलाएँ सिर्फ आधी आबादी नहीं, बल्कि राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं। मनुस्मृति के श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उल्लेख करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि महिलाएँ अब सिर्फ रसोई तक सीमित न रहकर विमान उड़ाने से लेकर खेलकूद और पर्वतारोहण तक हर क्षेत्र में देश का परचम लहरा रही हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व विकास की उपलब्धियों की चुकी करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को योजनाओं की बंदीत आज देश में करीब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कामय कर चुकी हैं। केवल शहरी ही नहीं, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी



आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए टोस कदम उठाए गए हैं। विषम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत नीतियों का परिणाम है।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी ने बताया कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना खुद का पक्का घर बनाने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे आर्थिक मदद मिलती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की सुविधा सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में

मिलती है। देश के सभी छोटे-बड़े किसानों को खेती के खर्च में मदद के लिए हर साल 6 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। ग्रामीण छत्तीसगढ़ के हर घर तक पाइप के जरिए साफ और शुद्ध पीने का पानी पहुँचाया जा रहा है। गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएँ वाले चूल्हे से आजादी दिलाने के लिए मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और सिलेंडर दिया जाता है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी देती है, जिससे बिजली का बिल जीरो हो जाता है और एकस्ट्रा बिजली से कमाई भी होती है।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 21 तक मांगी रिपोर्ट

■ बाल गृहों की पहचान बदलने की पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की पहल पर प्रदेश में संचालित बाल एवं बालिका संरक्षण गृह तथा बाल संरक्षण गृहों को नई, सकारात्मक और बालहितैषी पहचान देने की दिशा में पहल की गई है। डॉ. वर्णिका शर्मा की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव को पत्र जारी कर इन संस्थाओं के वर्तमान औपचारिक एवं संस्थागत नामों के स्थान पर सकारात्मक, प्रेरणादायक और बच्चों में अपनत्व की भावना विकसित करने वाले नाम रखने का आग्रह किया गया है।

आयोग ने जम्मू में बाल संरक्षण संस्थाओं के लिए प्रचलित पलाश और परिषा जैसे नामों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह सकारात्मक एवं गरिमापूर्ण नाम अपनाने की



अनुशंसा की है। आयोग का मानना है कि किसी संस्था का नाम बच्चों के मनोभाव और उसकी पहचान पर प्रभाव डालता है। इसलिए बाल संरक्षण गृहों की पहचान ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चों में हीनभावना के बजाय आत्मसम्मान, सुरक्षा और सकारात्मकता की भावना विकसित हो। आयोग ने सुझाव दिया है कि जिलों में नामकरण के दौरान स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रकृति, लोक परंपरा और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सकारात्मक एवं प्रेरणादायक नामों को प्राथमिकता दी जाए।

भाजपा ने घोषित किया

प्रकोष्ठ संकुल संयोजक व प्रकोष्ठ के प्रभारी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी

के प्रदेश अध्यक्ष

किरण सिंह देव

की सहमति से

प्रकोष्ठ संकुल

सं यो ज क -

को घोषणा की गई। यह नियुक्ति

तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रकोष्ठ संकुल संयोजक

सहसंयोजक लाभचंद बाफना,

मछुआरा प्रकोष्ठ कृष्णबिहारी

जोगेश लाम्बा, आर्थिक प्रकोष्ठ

राजेश अग्रवाल, एनजीओ प्रकोष्ठ

एस.डी. बड़गैया, बुनकर प्रकोष्ठ

श्रीमती सीमा साहू, विधि प्रकोष्ठ

जयप्रकाश चंद्रवंशी, चिकित्सा

प्रकोष्ठ डॉ. ललित माखीजा,

व्यापार प्रकोष्ठ श्रीचंद सुंदरानी,

ज्यवसायी प्रकोष्ठ प्रदीप सिंह,

आर.टी.आई. प्रकोष्ठ डॉ.

विजयशंकर मिश्रा, सांस्कृतिक

प्रकोष्ठ सुश्री मोना सेन, पंचायत

प्रकोष्ठ श्रीमती श्वेता शर्मा, नगरीय

निकाय प्रकोष्ठ देवजी भाई पटेल,

शिक्षा प्रकोष्ठ राजेश साहू तथा

सहकारिता प्रकोष्ठ विकांत सिंह

प्रकोष्ठ के प्रभारी बनाए गए हैं।

पोषण माह के सफल आयोजन को लेकर

राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के प्रभावी एवं सफल आयोजन को लेकर आज संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में अंतरविभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए पोषण माह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा, विभागीय समन्वय और मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जनभागीदारी के साथ मनया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी है। पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं तथा किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार के साथ समुदाय में स्वस्थ खान-पान और पोषण संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना है। बैठक में पोषण माह के दौरान



आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन सेवन, आंगनवाड़ी केन्द्रों में ताजा एवं गरम पका हुआ भोजन, सामुदायिक सहभागिता, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य हेतु नकद अंतरण जैसे विषयों पर विशेष रूप से गतिविधियाँ संचालित करने पर चर्चा हुई।

अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और गतिविधियों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए अंतरविभागीय समन्वय के साथ पोषण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर दिया। आंगनवाड़ी केन्द्रों, पंचायतों, विद्यालयों तथा समुदाय के माध्यम से पोषण जागरूकता को व्यापक बनाने और अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, अनुसूचित जाति विकास, आदिम जाति कल्याण, कौशल विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पोषण माह के दौरान समुदाय आधारित गतिविधियों, पोषण जागरूकता और डिजिटल मार्निटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में पोषण ट्रेकर के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों के विभिन्न पोषण संकेतकों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक ने पूछा पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से सवाल

भूपेश अपने शासनकाल के नौकरी के खेल का जवाब दें

■ युवाओं के सपनों का सौदा करने वाली कांग्रेस अब किस मुँह से युवाओं के हित की बात कर रही है? - भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य और उनके सपनों से जुड़े पीएससी घोटाले की जाँच में सामने आ रही जानकारीयाँ बेहद गम्भीर हैं। 2021 की भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने, चुनिंदा अभ्यर्थियों को लाभ पहुँचाने और राजनीतिक-प्रशासनिक प्रभाव वाले लोगों के रिश्तेदारों को फायदा पहुँचाने के आरोप सामने आए हैं। अब इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्कालीन निजी सहायक से जुड़े परिसरों सहित सात स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग

मामले की जाँच का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने कहा कि यह सवाल अब छत्तीसगढ़ के हर युवा का है। जिस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए, वह आज युवाओं के रोजगार और अधिकारों की बात किस नैतिक आधार पर कर रही है? जिस नौकरी को पाने के लिए छत्तीसगढ़ का गरीब और मध्यमवर्गीय युवा वर्षों तक मेहनत करता है, अगर उसी नौकरी की प्रक्रिया में पहले से तय अभ्यर्थियों, रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुँचाने का खेल हुआ है, तो यह केवल एक भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस बताए, यह कैसी युवा न्याय की राजनीति है?



उज्ज्वल दीपक ने कहा कि आज कांग्रेस के नेता युवाओं के रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और अवसरों की समानता पर बड़े-बड़े भाषण देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार के कार्यकाल की भर्ती प्रक्रिया पर गम्भीर आरोप सामने आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, दूसरी तरफ उसके शासनकाल की सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर ही नौकरी बेचने और चयन में पक्षपात के आरोप लगे हैं। यह कैसी विडंबना है कि जिस युवा को नौकरी पाने के लिए वर्षों तक किताबों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उसके सामने कथित रूप से सत्ता और पैसे का रास्ता खोल दिया गया!

दीपक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल दागते हुए कहा कि

बघेल को यह बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में पीएससी की पूरी चयन प्रक्रिया में ऐसी गम्भीर अनियमितताएँ कैसे हुई? उनके कार्यालय और तत्कालीन प्रशासन से जुड़े लोगों के नाम जाँच के दायरे में क्यों आ रहे हैं? क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस पूरे नेटवर्क की कोई जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर जानकारी नहीं थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जवाबदेही से मुँह क्यों छिपा रहे हैं? उज्ज्वल दीपक ने कहा कि कल तक कांग्रेस के नेता युवाओं से कहते थे कि उन्हें रोजगार चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का युवा पछा रहू है रोजगार चाहिए था, या रोजगार का बाजार बनाया गया था? कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल के इस कथित नौकरी के खेल का जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही युवाओं के भविष्य पर राजनीति करनी चाहिए।

योजनाओं की चर्चा करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि राज्य की शादीशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1,000 रुपये महतारी वन्दन योजना में सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए सरकार 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से (21 क्विंटल प्रति एकड़) धान की खरीदी करती है और आर्थिक मदद देती है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के उन परिवारों को सालाना आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके पास खेती के लिए खुद की कोई जमीन नहीं है। नियद नेछ्छानार योजना योजना में बस्तर के नक्सल प्रभावित और अंदरूनी गाँवों तक बिजली, पानी, राशन, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने की एक बड़ी पहल है। इसी प्रकार रानी दुर्गावती योजना, श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, सरस्वती साइकिल योजना आदि की भी चर्चा श्रीमती चौधरी ने की।

साथ ही संबंधित संस्थाओं में रहने वाले बच्चों, देखरेखकर्ताओं और अन्य दिहाधारकों से भी नामों को लेकर सुझाव लिए जाएँ, ताकि बच्चे अपनी संस्था की नई पहचान से आत्मीय रूप से जुड़ सकें।

आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर जिलों से प्रस्तावित नामों की सूची प्राप्त करने तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग की 21 सितंबर 2026 तक लिखित रूप से अवगत कराने का आग्रह किया है। आयोग की यह पहल बाल संरक्षण संस्थाओं को केवल प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखने के बजाय उन्हें बच्चों के सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक विकास के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और बाल संरक्षण गृहों से जुड़ी बच्चों की सोच और सामाजिक पहचान को अधिक सकारात्मक बनाने में मदद मिलेगी।

पिरदा की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी सरकार

ग्रामीणों की आपत्ति पर मंत्री चौधरी ने लिया फैसला

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के लिए चिन्हांकित पिरदा गांव की जमीन का अब सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।

बैठक में ग्रामीणों ने प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना था कि चिन्हांकित जमीन पर वे लंबे समय से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 20 प्रतिशत लोगों के मकान भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में जमीन अधिग्रहण होने से उनके सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

पिरदा में आरडीए द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए जमीन चिन्हांकित किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों और किसानों में चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों ने ग्रामसभा में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने की



मांग की थी।

ग्रामीणों की मांग को धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी को ग्रामीणों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार को विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।

मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कहा कि यदि ग्रामीण अपनी जमीन पर आवासीय प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं, तो उनकी इच्छा के खिलाफ वहां परियोजना नहीं लाई जाएगी। मंत्री ओपी चौधरी ने आरडीए को पिरदा की जमीन नहीं लेने के निर्देश देने की बात कही। सरकार के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की बात कही है।

कार्यालय कार्यापालन अभियंत्रण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

Office Phone. :- 07727-296695 Email ID :- ee-res.abhanpur@nic.in

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-11//
(प्रथम बार)

क्रमांक 2273/निविदा/ग्रा.यां.से./2026-27

बलौदाबाजार, दिनांक 31/08/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रतियोगिता दर पर दिनांक 14.09.2026 तक ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

सिस्टम डेंडर नं.	कार्य का विवरण	ठेके की अनुमानित लागत (लाख में)	ऑनलाइन निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि
1	2	3	4
198499	200 मी. टन क्षमता के गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण कार्य (विद्युतीकरण, सेनेटरी फिटिंग एवं बोरेखेल पम्प सहित), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तेलारी, वि.छ. -पलारी	24.94	14.09.2026

2/ निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2.13) यथा संशोधित व अन्य जानकारी वेबसाइट <http://eproc.cgstate.gov.in> में अथवा कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 31.08.2026 से देखी जा सकती है।

योगेश कुमार खाण्डे
ग्रा. या. सेवा संभाग - बलौदाबाजार
जिला बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.)

जी-262703057/5

सरकार के सामने जातिगत आरक्षण की कठिन परीक्षा

पूनम आर्. कौशिश

विरोध –प्रदर्शनों का दौर है। ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ नया राजनीतिक आकर्षण बनता दिख रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के बीच एक-दूसरे के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ सार्वजनिक टकराव यह बताने के लिए काफी है कि जाति का जित्न अब कितना विस्फोटक हो चुका है। विडंबना यह है कि सामाजिक न्याय तक पहुंचने के लिए जिस आरक्षण को एक सेतु की तरह देखा गया था, वही आज राजनीतिक बारूदी सुरंगों के ऊपर बने पुल में तबदील होता दिखाई दे रहा है। भारत में जाति-आधारित आरक्षण दशकों से ऐसा मुद्दा रहा है, जिसे छूना सरकारों के लिए राजनीतिक जोखिम मोल लेने जैसा रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। असंतोष केवल उन लोगों तक सीमित नहीं, जो आरक्षण से बाहर हैं। आरक्षण पाने वाले समुदाय भी अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, जबकि गैर-लाभार्थी वर्ग निष्पक्षता का सवाल उठा रहा है। आरक्षित वर्गों के भीतर ही अलग-अलग समुदाय पृष्ठ रहे हैं-हमें हमारा हिस्सा कब मिलेगा? वहीं सामान्य वर्ग का सवाल है-आरक्षण सामाजिक न्याय के अस्थायी उपाय से स्थायी अधिकार कब बन गया? यही वह मोड़ है जहां मोदी सरकार के सामने जातिगत आरक्षण की राजनीति का सबसे कठिन इम्तिहान खड़ा है। एक ओर यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकारी सहायता का आधार जाति नहीं, बल्कि आर्थिक वंचना हो। दूसरी ओर दलित समुदाय के 2 प्रमुख नेताओं, लोजपा के पशुपति कुमार पारस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, के बीच आरक्षण को लेकर टकराव ने भाजपा-एन.डी.ए. के लिए जातिगत समीकरणों को नई जटिलता उजागर कर दी है। मूल विवाद है ‘आरक्षण के भीतर आरक्षण’ का। सवाल यह है कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति के मौजूदा कोटे को भी उप-वर्गों में बांटा जाए, ताकि उन वर्गों के सबसे वंचित समुदायों को आरक्षण का सुनिश्चित हिस्सा मिल सके? पारस इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि एस.सी. आरक्षण की बुनियाद गरीबी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता है। आरक्षण को उपजातियों में बांटने से दलित समुदाय की राजनीतिक और सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। उनका सवाल सीधा है-जब आरक्षण का उद्देश्य जातिगत भेदभाव का मुकाबला करना है, तो आर्थिक कसौटी को इसमें क्यों जोड़ा जाए? मांझी का तर्क इसके विपरीत है। उनके अनुसार मौजूदा एस.सी. आरक्षण का लाभ सबसे वंचित दलित समुदायों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। अपेक्षाकृत मजबूत और बेहतर प्रतिनिधित्व वाले समूह आरक्षण के लाभ का बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं, जबकि सबसे पिछड़े समुदाय पीछे छूट रहे हैं। यहीं से आरक्षण की बहस एक नई राजनीतिक आग पकड़ती है। दोनों पक्षों के तर्कों में दम है और दोनों के पीछे एक असुविधाजनक सच्चाई भी। गरीबी जातिगत भेदभाव को मिटा नहीं देती लेकिन जाति अपने आप में गरीबी का प्रमाण भी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय का कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है, जबकि आरक्षित श्रेणी से बाहर का व्यक्ति बेहद गरीब हो सकता है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। इसे ऐतिहासिक बहिष्कार और सामाजिक भेदभाव के समाधान के लिए बनाया गया था। लेकिन दूसरी ओर, अवसरों के लिए लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक नई बेचैनी पैदा कर रही है। विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों में सीमित सीटों के लिए संघर्ष कर रही युवा पीढ़ी के एक हिस्से को आरक्षण सामाजिक न्याय की सीढ़ी की बजाय अवसर के रास्ते में खड़ी बाधा दिखाई दे सकता है। यही सरकार की असली दुविधा है

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)	(अगिण पु० भ० 267)
गवायुवेद शृंगमयेषु धेनूनां तैलं दद्यात्ससैन्धवम् । अतिसारे हर्दिद्व द्व पाठां चैव प्रापयेत् ॥ बिल्वमूलमपामार्गाधतकी क सपाटला । कुटज दन्तमूलेषु लेपातच्छूलनाश्रमम् ॥ (अगिण पु० अ० 262) अर्थात्- गाय के सींगों पर नमक और तेल लगावे। गाय बैलों में दस्तों का रोग हो तो दोनों हल्दियें और पाठा ये चीजें मिलाकर दे दो। पशुओं के दांतों में दर्द हो तो, अपामार्ग (जिसे ऊंगा, चिरचिटा किंवा पुठकंडा कहते हैं) आंवला, पाढ़ला, इन्द्र जौ इन सब को दातों की जड़ में लेप करे इत्यादि गो-चिकित्सा भी हमें पुराणों में मिलती है। विषचिकित्सा शरीषपुष्पस्य रसभावितं मरिचं सितम् । पाननस्याञ्जनाद्यैश्च विषं हन्यान्न संशयः ॥	अर्थात्- किसी भी जन्तुविशेष के खास कर सपं के विष को दूर करने के लिए सिरस के फूल के रस में भिंगोई हुई सफेद मिरचें पीने से सूचने से या आँखों डालने से विष दूर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक तरह की चिकित्साओं का-जिनसे कि गृहस्थ का सम्बन्ध प्रायः रहा करता है-अग्निपुराण, गरुडपुराण और मत्स्यपुराणादि में पर्यासरूपेण वर्णन मिल जाता है। यदि भारत के दरिद्र नारायण लोगों को पुराणों का समादर करने की अब भी सुधी आजाय तो वह बड़े सस्ते तरीके से स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं तथा स्वदेशी चिकित्सा-प्रणाली को भी उन्नत कर सकते हैं । स्वप्न-ज्ञान यह एक हमारा प्रधान शास्त्र था जिसके द्वारा हम भावी शुभाशुभघटनाओं का पता चला लिया करते थे। क्रमशः ...



एससीओ के मंच से मोदी ने चीन-पाकिस्तान को एक साथ धोया

नीरज कुमार दुवे

एससीओ शिखर सम्मेलन में वैसे तो सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने संबोधन में तमाम तरह के मुद्दे उठाये लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल मुद्दों की विविधता और सबको साथ लेकर चलने के जज्बे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही तमाम अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी यह देखकर हैरान हैं कि कैसे मोदी ने मंच पर साथ मौजूद चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कउधरे में खड़ा किया तो वहीं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सवाल पर चीन को भी आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद पर मोदी ने दो टुक कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं और आतंकवाद को अपनी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंक कभी किसी की रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता। वहीं कनेक्टिविटी के नाम पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौते को अस्वीकार करते हुए उन्होंने चीन को भी साफ संदेश दिया।

किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी को महज औपचारिक भागीदारी तक सीमित नहीं रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के 25 वर्षों की यात्रा को अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने के अवसर में बदलते हुए भारत का स्पष्ट एजेंडा सामने रखा। सिम्बोरिटी, कनेक्टिविटी और अर्पांच्युनिटी के जरिये मोदी का संदेश था कि अब केवल घोषणाओं और संवाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना होगा।

प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे धारदार हिस्सा आतंकवाद पर था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद



मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और इसके खिलाफ कार्रवाई केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आतंकवादी वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ, सुरक्षित ठिकानों और पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार करने से साफ इंकार किया। यह संदेश ऐसे मंच से आया, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्वयं मौजूद थे।

भारत की कूटनीतिक उपलब्धि यहीं समाप्त नहीं हुई। एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने पर स्वीकार की गई बिश्केक डिक्लेरेशन ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती दी। घोषणा और शिखर सम्मेलन के अन्य फैसलों में आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुरक्षा चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए यूनिवर्सल सेंटर संबंधी नियमों को मंजूरी देना सदस्य देशों के बीच समन्वय और सूचना आदान-प्रदान को मजबूत करने वाला कदम है।

भारत के लिए विशेष महत्व की बात यह भी रही कि अंग्रेजी को एससीओ के संस्थागत ढांचे में शामिल करने की दिशा में प्रगति हुई। साथ ही भारत द्वारा आगे बढ़ाई गई कई पहलों जैसे- एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, यंग साइटस्टि फोरम और यंग ऑथर्स कॉन्क्लेव को भी बिश्केक डिक्लेरेशन में स्थान मिला। यह संकेत है कि भारत

ज्ञान/मीमांसा

ब्रिक्स सम्मेलन: क्या विस्तार के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल पाएगा भारत?

अभिनय आकाश

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली का भारत मंडपम 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। वर्ष 2006 में बने इस समूह के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित यह बैठक बेहद अहम है। दुनिया की 45 प्रतिशत से ज्यादा आबादी और करीब 30 फीसदी वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला यह मंच आज एक ताकतवर गुट बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेंगे, तो भारत के सामने कई कूटनीतिक चुनौतियां होंगी। बदलते वैश्विक व्यापार नियमों और पश्चिम एशिया के संकट के बीच नई दिल्ली के लिए यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और ब्रिक्स को पश्चिमी-विरोधी धड़े में तब्दील होने से बचाने का एक बड़ा इम्तिहान होगा।

भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्राज़ील से ब्रिक्स की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली। अध्यक्षता की आधिकारिक थीम – मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण से प्रेरित होकर, नई दिल्ली ने अपनी अध्यक्षता को मानवता सर्वोपरि की भावना पर आधारित, ईसान-केंद्रित नज़रिए के इर्द-गिर्द तैयार किया है। नेताओं का यह दो-दिन का शिखर सम्मेलन, साल भर चले एक बड़े डिप्लोमैटिक अभियान का नतीजा है। भारत की अध्यक्षता में, देश भर के 25 शहरों में 350 से ज्यादा मंत्री-स्तरीय, चर्किंग-ग्रुप और ट्रैक-टू बैठकें हुईं। इन तैयारियों में तीन मुख्य पहलु शामिल थे- राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय गवर्नेंस, और सांस्कृतिक व लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान। इनसे पहले हुई अहम बैठकों में मई में नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और अगस्त में पुणे में ब्रिक्स इन्फर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ट्रैक की बैठक शामिल हैं। नई दिल्ली का यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह इस रूप के औपचारिक रूप से ब्रिक्स+ में विस्तार के बाद नेताओं का पहला पूर्ण-स्तरीय शिखर सम्मेलन है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे संस्थापक सदस्यों के अलावा, अब मिस्र, इथियोपिया,



ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य बन गए हैं। सम्मेलन के विस्तारित सत्रों में कई आमंत्रित सदस्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे जिनमें बिस्मटेक, आसियान, अफ्रीकी संघ और खाड़ी सहयोग परिषद के नेता शामिल हैं।

जब भारतीय राजनयिक शिखर सम्मेलन के घोषणा-पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक है। 11 सदस्यों वाले इस बड़े समूह में इस बात को लेकर बुनियादी मतभेद हैं कि ब्रिक्स को कैसा होना चाहिए। मांस्को और बीजिंग ब्रिक्स को पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने, जी7 के प्रभुत्व का मुकाबला करने और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा तैयार करने के लिए एक मुख्य भू-राजनीतिक साधन के रूप में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस समूह में पश्चिमी प्रतिबंधों और सुरक्षा गठबंधनों का मुकाबला

करने की क्षमता है। इसके विपरीत, भारत इस बात को नहीं मानता कि ब्रिक्स को पश्चिमी-विरोधी टकराव वाले गठबंधन के तौर पर काम करना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया है: ब्रिक्स गैर-पश्चिमी है, पश्चिमी-विरोधी नहीं। भारत का रणनीतिक हित इस बात में है कि वह ब्रिक्स का इस्तेमाल मौजूदा ग्लोबल संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक — में सुधार लाने के लिए करे, न कि उन्हें खत्म करके ध्रुवीकृत और कोल्ड-वॉर जैसे गुटों में बंटी दुनिया बनाए। संतुलन बनाने की इस कोशिश में भारत की एक खास स्थिति है: वह अकेला ऐसा देश है जो ब्रिक्स और ब्राड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं दोनों का सक्रिय सदस्य है। एक तरफ भारत इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सप्लाई चेन के मामलों में ब्रांशिंगटन और यूरोप

की राजधानियों के साथ मिलकर काम करता है, तो दूसरी तरफ वह नई दिल्ली में रूस, चीन और ईरान के साथ भी एक ही मेज पर बैठता है।

इस समिति की मेजबानी करने के लिए नई दिल्ली को दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ जटिल द्विपक्षीय मतभेदों को संभालना होगा और साथ ही बहुपक्षीय नतीजों की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।

सैन्य बातचीत के बाद लाइन ऑफ़ एक्जुअल कंट्रोल (एलएसी) पर धीरे-धीरे सेना पीछे हटने के बावजूद, भारत और चीन के बीच बुनियादी तनाव अभी भी बना हुआ है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सीमा सुरक्षा और दक्षिण एशिया में बीजिंग का बढ़ता प्रभाव, दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। ब्रिक्स के संदर्भ में, भारत इस बात को लेकर सतर्क है कि चीन इस बड़े हुए समूह का इस्तेमाल अपनी क्षेत्रीय पहलों को आगे बढ़ाने या ब्रिक्स को बीजिंग की विदेश नीति के लक्ष्यों का समर्थन करने वाला मंच बनाने के लिए न करे।

मुश्किल वक्त में ही चरित्र की पहचान होती है, हालात से ऊपर उठना ही कारगर सूत्र

लियो टॉल्स्टॉय

मनुष्य अक्सर यह सोचकर जीवन जीता है कि यदि परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी, तभी वह सुखी और सफल हो सकेगा। वह चाहता है कि रास्ते में कोई बाधा न आए, लोंग उसके अनुसार व्यवहार करें और भविष्य उसकी योजनाओं के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन, जीवन कभी इना सरल नहीं होता। हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम दूसरों के निर्णयों को नहीं बदल सकते और हर कठिनाई को अपनी इच्छानुसार समाप्त नहीं कर सकते। फिर भी, इन सबके बीच हमारे पास एक ऐसी स्वतंत्रता रहती है, जिसे कोई परिस्थिति हमसे नहीं छीन सकती। वह है अपने आचरण को चुनने की स्वतंत्रता। युद्ध हो या शांति, समृद्धि हो या अभाव,



सफलता हो या असफलता, मनुष्य का वास्तविक चरित्र इस बात से सामने आता है कि वह इन परिस्थितियों के बीच कैसा व्यवहार करता है। अनुकूल समय में शांत और विनम्र बने रहना आसान हो सकता है, लेकिन मुश्किल समय में भी अपने भीतर की मानवता को बचाए रखना कहीं अधिक कठिन है।

जब जीवन हमारी योजनाओं को तोड़ देता है, तब हमारे सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि अब हम क्या करेंगे? क्या हम परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, या जो कुछ हमारे हाथ में है, उसके आधार पर

आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन दूसरों के निर्णयों से तय हो रहा है। कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है और कभी ऐसी घटना घट जाती है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। उस समय मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों का शिकार समझने लगता है। लेकिन, कठिनाइयों के बीच भी उसके पास अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और यह तय करने की शक्ति होती है कि वह अपने भीतर कड़वहट को जगह देगा या समझ व धैर्य को।

जीवन की सबसे बड़ी भूल शायद यही है कि हम परिणामों को अपने नियंत्रण में मान लेते हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। हम प्रेम कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला उसी तरह प्रेम करेगा, यह तय नहीं कर सकते। इसलिए, जीवन की शांति इस बात

में नहीं है कि हमारे साथ हमेशा वही हो, जो हम चाहते हैं। शांति इस समझ में है कि जो हमारे हाथ में है, उसे पूरी ईमानदारी से करें और जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखें।

परिस्थितियां हमारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा लिख सकती हैं, लेकिन उस कहानी में हम किस तरह के मनुष्य बने रहेंगे, इसका चुनाव काफी हद तक हमारा अपना होता है। इसलिए, जीवन को केवल उन घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखना चाहिए, जिनहें हम बदलना चाहते हैं। उसे उन अवसरों के रूप में भी देखना चाहिए, जिनमें हम अपने चरित्र को आकार देते हैं। हम हर परिस्थिति को नहीं चुन सकते, लेकिन उसके बीच अपने आवरण को चुन सकते हैं। और, कई बार यही छोटा-सा चुनाव हमारे पूरे जीवन का अर्थ बदल देता है।

आज का इतिहास

- 1650 इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच डनबर की लड़ाई हुआ।
- 1783 अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया।
- 1791 फ्रांस की नेशनल एसेंबली ने फ्रांसीसी संविधान को पारित किया।
- 1833 अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र ‘न्यूयार्क सन’ बेंजामिन एग डे के द्वारा शुरू किया गया था।
- 1939 ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ।
- 1943 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया।
- 1971 कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना।
- 1984 दक्षिण अफ्रीका ने संविधान को अंगीकार किया।
- 1984 दक्षिण फिलिपीन्स में आये एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।
- 1998 नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाये जाने पर प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की।
- 1998 स्विस् एयर का न्यूयॉर्क से जेनेवा जा रहा हवाई जहाज, नोवा स्कोटिया के पास समुद्र में गिर गया। इस जहाज़ ने हादसे के महज़ एक घंटे पहले ही उड़ान भरी थी।
- 2003 पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय।
- 2004 रूसी सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं के कब?जे से स्कूल मुक्त कराया।
- 2006 यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन समाप्त। भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- 2007 चीन के झिंगजियांग प्रान्त में चीनी व जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके सबसे छोटे पुत्र अराफात रहमान कोको को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
- 2008 राजेन्द्र कुमार पंचौरी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अन्तर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) का पुनः प्रमुख चुना गया।
- 2009 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. रेड्डी की हेलीकाप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी।
- 2014 भारत और पाकिस्तान में अचानक आयी बाढ़ के कारण दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत।

एससीओ समिट : मियां शहबाज शरीफ, तस्वीर काटने से हकीकत नहीं बदलती

विनोद पाठक

कूटनीति अति गंभीर विषय है। इसमें शब्दों का भी बजन होता है और तस्वीरों का भी, लेकिन जब किसी देश की सरकार अंतरराष्ट्रीय मंच की आधिकारिक तस्वीर को इस तरह काट-छोटकर पेश करे कि उसका अपना नेता ज्यादा प्रमुख दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

बिश्केक में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई एक तस्वीर इसी वजह से चर्चा में आ गई। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और कुछ अन्य नेताओं को फ्रेम से बाहर कर दिया गया था, जबकि सम्मेलन की मूल तस्वीर में सभी नेता मौजूद थे। हालांकि, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी तस्वीर अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से साझा कर दी। यहां सवाल केवल फोटो एडिट करने का नहीं है। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी देश को अपनी जगह साबित करने के लिए तस्वीर काटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तस्वीर काटने से किसी देश का कद बड़ा नहीं होता। किसी नेता को तस्वीर से हटाने से वह अंतरराष्ट्रीय मंच से हट नहीं जाता।

यह घटना इसलिए भी दिलचस्प है कि मूल तस्वीर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, यानी जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय

ने अपनी पोस्ट में नहीं दिखाया, उसे दुनिया के दूसरे नेताओं और आधिकारिक स्रोतों ने दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तस्वीर साझा की, जिसमें शहबाज शरीफ समेत सभी नेता मौजूद थे।

इसके बाद पाकिस्तान की पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे और आलोचना तेज हो गई। बाद में शरीफ ने पूरी तस्वीर साझा कर मामले को संभालने की कोशिश की। यहीं से बात फोटो से आगे निकल जाती है। अगर किसी देश की सरकार को लगता है कि भारत को तस्वीर में दिखाने से उसकी अपनी छवि कमजोर होगी तो यह सोच खुद में काफी कुछ कहती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी की मौजूदगी को मिटाने का सबसे आसान तरीका फोटो एडिट करना हो सकता है, लेकिन उसकी राजनीतिक मौजूदगी को मिटाना संभव नहीं है।

यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में लंबे समय से तनाव है। दोनों देशों के बीच युद्ध हुए हैं। आतंकवाद बड़ा विवाद रहा है। सीमा पर लगातार तनाव बना रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से दबाव है। विदेशी कर्ज, महंगाई, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं वहां लगातार चर्चा में रही हैं। ऐसे माहौल में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता को रोजगार, स्थिरता और बेहतर जीवन देना है। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर किसी



दूसरे देश के प्रधानमंत्री को तस्वीर से हटा देना शायद घरेलू राजनीति में कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन इससे न महंगाई कम होती है और न अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। देश तस्वीरों से नहीं, अपनी आर्थिक और संस्थागत ताकत से बड़ा होता है।

दरअसल, पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में भारत विरोधी राजनीति की भूमिका बहुत बड़ी रही है। 1947 के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे। 1948, 1965, 1971 और 1999 में दोनों देश युद्ध लड़ चुके हैं। हर बार पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। 1971 पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बड़ी

संख्या में पाकिस्तानी सैन्यकर्मी और अन्य कर्मी युद्धबंदी बने। इतिहास का उद्देश्य किसी समाज को हमेशा अपमानित करना नहीं होता। इतिहास का उद्देश्य यह समझना होता है कि गलतियों से क्या सीखा जाए? पाकिस्तान के लिए भी यही बात लागू होती है। भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक माहौल बनाकर वह अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से लंबे समय तक ध्यान नहीं हटा सकता।

भारत और पाकिस्तान के व्यापार को लेकर अक्सर बहुत बड़ा-चढ़ाकर बातें कही जाती हैं। तथ्य यह है कि भारत ने 15 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया था। पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया था। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निर्लिंबित कर दिया।

अब दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध लगभग ठप हैं। पानी का मुद्दा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अप्रैल 2025 में भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया। भारत ने पानी को सुरक्षा और आतंकवाद के संदर्भ में देखने का संदेश दिया

चीन की जिद से तिब्बत में बदलता हिमालय

विनोद पाठक

पड़ोसी देश नेपाल के रसुवा जिले में आई अचानक बाढ़ या कहेँ सुनामी ने एक बार फिर हिमालय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तिब्बत की तरफ से आए तेज पानी ने सीमावर्ती इलाकों में भारी नुकसान किया। सड़कें और पुल टूट गए। पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। इस घटना की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि, शुरुआती आकलन में हिमस्खलन, चट्टानों के खिसकने और ग्लेशियर से जुड़े जलभराव की आशंका जताई गई है। इसलिए इस बाढ़ को सीधे चीन के निर्माण कार्य का नतीजा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है। क्या तिब्बत में तेजी से हो रहा निर्माण और बदलता मौसम आने वाले समय में हिमालयी इलाकों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं? यह सवाल केवल नेपाल का नहीं है। इसका सीधा संबंध भारत से भी है। दरअसल, तिब्बत को अक्सर एशिया का ‘वाटर टॉवर’ कहा जाता है। यहां से निकलने वाली कई बड़ी नदियां भारत, नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे देशों तक जाती हैं। इन नदियों का पानी खेती, पीने के पानी और बिजली के लिए बेहद जरूरी है। समस्या यह है कि हिमालय तेजी से बदल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पास नई झीलें बन रही हैं। इन झीलों के अचानक टूटने पर नीचे के इलाकों में कुछ ही घंटों में बड़ी बाढ़ आ सकती है। यही कारण है कि हिमालय में होने वाली हर बड़ी प्राकृतिक घटना की गंभीरता से देखने की जरूरत है। एक तथ्य यह भी है कि चीन तिब्बत में सड़कें, रेलवे, सुरंग और बांध बना रहा है। इसका एक बड़ा कारण सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ना और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना है। यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन की विशाल पनबिजली परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है। चीन का कहना है कि

ऐसी परियोजनाएं उसके विकास और ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी हैं, लेकिन भारत और नेपाल के लिए चिंता का विषय यह है कि इन परियोजनाओं का असर नीचे की ओर बहने वाले पानी पर क्या होगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय का भूगोल बेहद संवेदनशील है। यहां बड़े पैमाने पर पहाड़ काटने, सुरंग बनाने और निर्माण करने से भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सवाल चीन के विकास करने के अधिकार का नहीं है। सवाल है कि क्या इतना बड़ा निर्माण पर्याप्त पर्यावरणीय सावधानी के साथ हो रहा है? दूसरा, सीमा पर नदियों के मामले में सबसे जरूरी चीज समय पर जानकारी है। यदि ऊपर के इलाके में अचानक ग्लेशियर झील टूटती है या पानी का बहाव बहुत बढ़ता है तो नीचे बसे देशों को तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। भारत और चीन के बीच नदियों के जलस्तर और बहाव से जुड़े आंकड़े साझा करने की व्यवस्था रही है, लेकिन कई बार इस व्यवस्था में रुकावट आई है। यह स्थिति चिंता पैदा करती है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद जानकारी मिलने का कोई फायदा नहीं। जानकारी बाढ़ आने से पहले चाहिए। नेपाल और भारत को समय रहते पता हो कि ऊपर के क्षेत्र में क्या हो रहा है तो हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। रसुवा की घटना में नेपाल को भारी नुकसान हुआ है। सीमावर्ती सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। पनबिजली परियोजनाओं पर भी असर पड़ा है। नेपाल की समस्या यह है कि उसके पास संसाधन सीमित हैं। पहाड़ी इलाकों में सड़क या पुल बनाना पहले ही महंगा है। बार-बार प्राकृतिक आपदाओं में वही ढांचा टूट जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है। नेपाल को इस मामले में चीन से सीधे टकराव की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी जानकारी जरूर मांगनी चाहिए। उसे यह जानने का अधिकार है कि सीमा के दूसरी तरफ कौन-से बड़े निर्माण हो रहे हैं? उनका पानी तथा पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है।

सिंधु जल संधि: हेग के फैसले से भारत-पाकिस्तान में नई जंग

के.एस. तोमर

सिंधु जल संधि पर हेग के फैसले से राजनीतिक और कानूनी लाभ उठाने की पाकिस्तान की उम्मीदों को भारत ने पूरी तरह नकार दिया है। नई दिल्ली ने मध्यस्थता न्यायालय को गैर-कानूनी ढंग से गठित संस्था बताते हुए उसके फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले को लागू करने का कोई सवाल नहीं और सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है। हेग न्यायाधिकरण का कहना है कि भारत 1960 की संधि से बंधा है और वह एकरतफा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां स्थगित नहीं कर सकता। इसके विपरीत, भारत उस न्यायाधिकरण के अधिकार-क्षेत्र को ही खारिज करता है जिसके तहत फैसला दिया गया। इसलिए विवाद केवल संधि की व्याख्या का नहीं, बल्कि न्यायाधिकरण के कानूनी अधिकार का है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है। सिंधु का पानी उसकी करीब 80 प्रतिशत कृषि और 1.6 करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सहारा देता है। भारत यह पक्षिमी नदियों-चिनाब, झेलम और सिंधु, पर भंडारण और जलविद्युत ढांचे का विस्तार करता है, तो उसके पास जल प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता बढ़ेगी।

भारत का कटोर रुख क्यों = भारत का रुख केवल रतले परियोजना तक सीमित नहीं है। 1960 में जब संधि हुई थी तब भारत-पाकिस्तान के संबंधों और क्षेत्र की भू-राजनीतिक परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। बाद के दशकों में दोनों देशों के संबंध लगातार बिगड़े हैं। सुरक्षा सांकेतिक और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह टकराव और गहरा हुआ है। नई दिल्ली अब संधि के तहत अपने हिस्से में उपलब्ध जल के अधिक उपयोग और जलविद्युत परियोजनाओं के विकास की स्वतंत्रता चाहती है। हेग के फैसले को स्वीकार करने का अर्थ भारत के लिए उस न्यायाधिकरण के अधिकार को मान्यता देना होगा, जिसे वह गैर-कानूनी मानता है। इससे संधि के स्थगन



संबंधी उसके रुख पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए नई दिल्ली के लिए फैसले को स्वीकार करना रणनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से कठिन है।

हेग का फैसला और रतले परियोजना = मध्यस्थता न्यायालय ने संधि को स्थगित करने के भारत के आधारों को खारिज करते हुए कहा है कि समझौता अभी भी प्रभावी है। उसने चिनाब पर रतले जलविद्युत परियोजना को लेकर अंतरिम उपाय लागू किए हैं। इसके तहत बांध की दीवार और विद्युत जल-प्रवेश ढांचे के कुछ हिस्सों पर निर्धारित स्तर से ऊपर कंक्रिट डालने के काम को सीमित किया गया है। यह रोक तटस्थ विशेषज्ञ के अंतिम फैसले और उसके बाद 90 दिनों तक प्रभावी रहने वाली है।

भारत ने खींचो कानूनी सीमा = भारत का कहना है कि न्यायाधिकरण का गठन सिंधु जल संधि में तय विवाद समाधान व्यवस्था के विपरीत हुआ है। भारत ने कार्रवाई में भाग लेने से भी इंकार किया है। नई दिल्ली का तर्क है कि न्यायाधिकरण उन विवादों पर अधिकार नहीं जता सकता, जिनका समाधान संधि में तय तंत्र के तहत होना चाहिए। उसके अनुसार, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत के संप्रभु निर्णयों को निर्धारित नहीं कर सकती और न ही यह तय कर सकती है कि वह अपनी जलविद्युत परियोजनाओं का विकास किस प्रकार करे। भारत ने मध्यस्थता न्यायालय और तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रियाओं के समानांतर चलने पर भी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान की कानूनी बढ़त, व्यावहारिक दुविधा

= पाकिस्तान के लिए फैसला इस दावे को मजबूत करता है कि भारत एकरतफा तौर पर संधि को स्थगित नहीं कर सकता। इससे इस्लामाबाद को भारतीय परियोजनाओं को चुनौती देने और अपने जल अधिकारों की रक्षा का दावा करने के लिए अतिरिक्त कानूनी आधार मिलता है। रतले परियोजना पर अंतरिम रोक पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन कानूनी जीत और उसके वास्तविक क्रियावन्धन में बड़ा अंतर है। न्यायाधिकरण भारत में निर्माण कार्य को भौतिक रूप से रोक नहीं सकता। यदि नई दिल्ली उसके अधिकार-क्षेत्र को अस्वीकार करती रहती है तो पाकिस्तान के पास भारत को फैसला मानने के लिए मजबूर करने के सीमित साधन ही होंगे। पाकिस्तान की कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जलविद्युत सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर हैं। इसलिए लंबे समय तक चलने वाला जल विवाद उसके लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन सकता है।

असल लड़ाई अब शुरू = हेग का फैसला सिंधु जल विवाद का समाधान नहीं करता, उसने इसे और गहरा कर दिया है। इस्लामाबाद संधि को बाध्यकारी मानता है, जबकि नई दिल्ली इसे स्थगित मानती है। न्यायाधिकरण अपने अधिकार का दावा करता है, जबकि भारत उस अधिकार को ही नकारता है। रतले परियोजना तत्काल टकराव का केंद्र है लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है-क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ऐसे देश पर दायित्व थोप सकता है, जिसने उसके अधिकार-क्षेत्र को ही स्वीकार नहीं किया है?

जो संधि कभी भारत-पाकिस्तान संबंधों में सहयोग का दुर्लभ उदाहरण थी, वही अब दोनों देशों के रणनीतिक टकराव का केंद्र बन गई है। हेग के फैसले ने खाई पाटने की बजाय यह साबित कर दिया है कि दोनों देशों के बीच यह खाई पहले से कहीं अधिक चौड़ी हो चुकी है।

सत्येंद्र प्रताप सिंह

आरक्षण का सवाल एनडीए के भीतर अब गंभीर टकराव का कारण बनता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीवन राम मांझी के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि बात एक-दूसरे से इस्तीफा मांगने तक पहुंच गई है। चिराग ने मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से इस्तीफे की मांग की, तो मांझी ने पलटवार करते हुए चिराग से पहले खुद इस्तीफा देने की चुनौती दे दी।

यह सिर्फ दो नेताओं की बयानबाजी नहीं है। इसके पीछे अपने-अपने सामाजिक आधार को साधने और दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश भी दिखाई देती है। चिराग पासवान का स्पष्ट रुख है कि एससी-एसटी आरक्षण को क्रीमी लेयर से जोड़ना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि आरक्षण आर्थिक गरीबी दूर करने की योजना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव से पैदा हुई असमानता को दूर करने का संवैधानिक माध्यम है। चिराग का कहना है कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव रहा है, इसलिए वंचित में आर्थिक आधार जोड़ना उचित नहीं होगा। वह आरक्षण के भीतर भी बंटवारे के खिलाफ हैं और मानते हैं कि इससे अनुसूचित जातियों की सामूहिक राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है।

दूसरी ओर जीवन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन का तर्क है कि आरक्षण का लाभ सभी वंचित समूहों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। कुछ समुदायों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिला है, जबकि कई जातियां अब भी पीछे हैं।

इसीलिए मांझी खेमे की ओर से आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण यानी ‘कोटे में कोटा’ की मांग की जा रही है। तर्क यह है कि आरक्षण का लाभ उन समुदायों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से इससे अपेक्षाकृत वंचित रहे हैं। संतोष सुमन ने भी आरक्षण की समीक्षा का अर्थ आरक्षण समाप्त करना नहीं, बल्कि उसका लाभ अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाना बताया है। यानी विवाद केवल यह नहीं है कि आरक्षण रहे या न रहे। असली बहस यह है कि आरक्षण का लाभ किसे और कितना मिले।



उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का आरक्षण को लेकर रुख मांझी की बहस से मिलाता-जुलता दिखाई देता है। राजभर भी इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उन वर्गों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे, जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

अब एनडीए के भीतर तस्वीर दिलचस्प है। एक तरफ चिराग मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के प्रति सावधान कर रहे हैं, दूसरी तरफ मांझी और राजभर आरक्षण के भीतर नए बंटवारे और पुनर्वितरण की जरूरत बता रहे हैं।

राजनीति में सवाल यह भी होता है कि किसी विवाद का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? चिराग, मांझी और राजभर तीनों एनडीए के घटक दलों से जुड़े हैं। ऐसे में एक ही गठबंधन के भीतर आरक्षण को लेकर अलग-अलग आवाजें उठाना केवल वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश भी हो सकती है।

लेकिन इसे सीधे एनडीए की ‘नूराकुशती’ कहना अभी जल्दबाजी होगी। चिराग और मांझी के बीच राजनीतिक मतभेद वास्तविक भी हो सकते हैं और दोनों अपने-अपने सारक्षक आधार को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र रणनीति बना रहे हों, इसकी भी पूरी संभावना है।

इस सियासी नूराकुशती का सबसे बड़ा संभावित लाभ फिलहाल एनडीए को दिखाई देता है। चिराग पासवान आरक्षण के मौजूदा स्वरूप की रक्षा की आवाज बनकर अपने सामाजिक आधार को मजबूत कर सकते हैं, जबकि मांझी और राजभर आरक्षण के लाभ से अपेक्षाकृत वंचित दलित-पिछड़े समूहों के बीच अपनी पकड़ बनाने की

है। यही बदलाव पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से गंभीर है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने इसे आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई बताया। इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर केवल बयान जारी करने तक सीमित रहने के बजाय सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी जवाब देने को तैयार है। असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले आतंकवादी ढांचे के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करता है? अगर इसका जवाब हां में आता है, तभी दोनों देशों के बीच संबंधों में स्थायी सुधार की कोई संभावना बन सकती है।

भारत की ताकत केवल इस बात में नहीं है कि वह पाकिस्तान से बड़ा देश है। भारत की वास्तविक ताकत उसकी अर्थव्यवस्था, बड़ी घरेलू बाजार क्षमता, तकनीकी क्षमता, अंतरिक्ष कार्यक्रम, डिजिटल ढांचे और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बढ़ते संबंधों में है। आईएमएफ के आंकड़े भारत की मजबूत विकास स्थिति को दिखाते हैं। 2026 के लिए आईएमएफ ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि करीब 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान दिया है। एक बात स्पष्ट है, भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका अब केवल दक्षिण एशिया

तक सीमित नहीं है। ऐसे में किसी एससीओ तस्वीर से भारत के प्रधानमंत्री को काट देने से भारत की भूमिका कम नहीं हो जाती। एससीओ की तस्वीर काटने की घटना को बहुत बड़ा कूटनीतिक संकट कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इसे पूरी तरह मामूली घटना मानकर छोड़ देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह बताती है कि सोशल मीडिया अब कूटनीति का हिस्सा बन चुका है। सरकारें एक तस्वीर से भी संदेश देने की कोशिश करती हैं।

इसलिए आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में छोटी-सी गलती भी अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती है। पाकिस्तान के लिए इस घटना में एक आसान सबक है, तस्वीर में किसी को हटाना आसान है, लेकिन दुनिया की राजनीति में किसी देश की भूमिका को हटाना आसान नहीं। भारत की वास्तविक ताकत किसी फोटो में नहीं है, वह उसकी अर्थव्यवस्था, संस्थाओं, सैन्य क्षमता, तकनीक और दुनिया के साथ बढ़ते संबंधों में है। पाकिस्तान की असली चुनौती भी किसी तस्वीर में नहीं है। वह उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं में है। इसलिए बेहतर होगा कि इस्लामाबाद फोटोशॉप की राजनीति से बाहर निकले। तस्वीर काटने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत बदलने के लिए नीति बदलनी पड़ती है।

चिराग-मांझी-राजभर : आरक्षण पर लड़ाई या एनडीए की नूराकुशती?

कोशिश कर सकते हैं। यानी एक ही गठबंधन के भीतर अलग-अलग नेता अलग-अलग सामाजिक वर्गों को साध रहे हैं और इसका व्यापक राजनीतिक लाभ एनडीए को मिल सकता है।

खासकर भाजपा के लिए यह स्थिति इसलिए उपयोगी हो सकती है कि उसे सीधे आरक्षण पर अपना कोई विवादास्पद रुख लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि उसके सहयोगी ही अलग-अलग सामाजिक समूहों के सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर इसका नुकसान विपक्ष को हो सकता है, क्योंकि एनडीए के भीतर से ही आरक्षण के पक्ष और उसके पुनर्वितरण- दोनों की आवाजें आने से विपक्ष के लिए भाजपा को एकरतफा ‘आरक्षण विरोधी’ बताना आसान नहीं रहेगा।

हालांकि इसका उलटा असर भी संभव है। यदि विवाद बयानबाजी से आगे बढ़कर गठबंधन के भीतर स्थायी दरार, दलित वोटों के विभाजन और सहयोगी दलों के बीच अविश्वास में बदल गया, तो नुकसान एनडीए को ही हो सकता है। इसलिए फिलहाल यह लड़ाई जितनी चिराग बनाम मांझी-राजभर की दिखाई दे रही है, उतनी ही यह दलित और पिछड़े वोटों के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई भी है।

यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। क्या एनडीए के भीतर आरक्षण को लेकर वास्तव में वैचारिक मतभेद हैं या फिर अलग-अलग सहयोगी अपने-अपने वोट बैंक को साधने की तैयारी कर रहे हैं? उने आने वाले चुनावों को देखते हुए दलित, अति-दलित, पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल और तेज हो सकता है। आरक्षण इसी सामाजिक राजनीति का सबसे प्रभावशाली मुद्दा है।

यही वजह है कि इस विवाद को केवल नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी रणनीति—तीनों की राजनीति दिखाई देती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है— यह आरक्षण के भीतर न्याय की वास्तविक लड़ाई है या एनडीए के भीतर चल रही ऐसी सियासी नूराकुशती, जिसका अंतिम लाभ गठबंधन को और नुकसान विपक्ष को हो सकता है?

कनाडा अपने स्वाभिमान की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा

मनinder सिंह गिल

कनाडा इन दिनों इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमरीका के साथ व्यापार वार्ता का टूटना सिर्फ टैरिफ या बाजार तक पहुंच का विवाद नहीं, यह इस बात की परीक्षा की घड़ी है कि क्या कनाडा भारी आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी संप्रभुता, अपने श्रमिकों, व्यवसायों और अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा कर सकता है? प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार द्वारा उस समझौते को अस्वीकार करना पूरी तरह से सही था, जो कनाडा की स्वतंत्रता से समझौता करता, देश के प्रमुख उद्योगों को कमजोर करता या फ्रेंच भाषा और कनाडाई संस्कृति को नुकसान पहुंचाता। ये चीजें सौदेबाजी के लिए नहीं हैं। ये हमारे देश की पहचान की नींव हैं। कनाडा ने पूरी गंभीरता और नेक नीयत से बातचीत की। लेकिन नेक नीयत से बात करने का अर्थ यह नहीं कि दादागिरी और अन्यायपूर्ण शर्तों को स्वीकार कर लिया जाए। जब अंतिम समय में शर्तें बदल दी गईं और उन्होंने कनाडा की सीमाओं को लांघा, तो सरकार ने बातचीत वहीं रोक दी। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है कि दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रमिकों का संरक्षण करना और सीमा के दोनों ओर समृद्धि लाना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री कार्नी के इस जवाब को केवल एक घटना पर दी गई प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह उसी सोच का वास्तविक रूप है, जो उन्होंने जनवरी में दावोस में ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ में रखी थी। दावोस में कार्नी ने चेतावनी दी थी कि वैश्विक माहौल बढ़े उथल-पुथल है और दोनों देशों के लाभ के लिए व्यापार समझौता अभी भी संभव है लेकिन उसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का सम्मान करना, श्रम

भारी बरसात और अधूरी योजनाओं ने खोली निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल

कोरबा। तेज बारिश ने कोरबा नगर पालिक निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। प्री मानसून की तैयारी के दावे धरे के धरे रह गए और पांश इलाकों तक पानी प्रवेश कर गया। दादर नाले के ऊपर से एक बोलेरो के बहने की तस्वीर सामने आई, तो सिटी के बीच मौजूद कई घरों में पानी भर गया। लोग घरों से पानी बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। सर्वमंगला कनबेरी मार्ग पर पुनर्वास ग्राम जटराज के समीप ओवर बर्डन का मलबा ढहकर सड़क पर बिखर गया।



कार इसके नीचे दब गई थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। बाल-बाल उनकी जान बची। पिछले वर्ष तक भी सीतामणी जैसे इलाकों में पानी भरने की समस्या

थी, लेकिन इस वर्ष हुई अधिक बारिश के कारण लोग ज्यादा परेशान हुए। कई इलाके ऐसे रहे, जहां 3 फीट से भी अधिक पानी भर

गया। ड्रेनेज सिस्टम के ध्वस्त होने से लोग खاسे नाराज हैं। इस वर्ष हुई अधिक परेशानी से लोगों को पुरानी अधूरी योजनाएं याद आ रही हैं और वह

कहीं घरों तक घुसा पानी तो कहीं गाड़ियां दबी

निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाता तो इन परिस्थितियों को टाला जा सकता था। दूसरी तरफ निगम प्रशासन की ओर से योजना बनाकर काम करने की बातें कही गयी हैं। अतिक्रमण को भी इसका कारण बताया गया है। बड़े नालों के ऊपर ही अतिक्रमण कर लिया गया है। जिससे जल निकासी बाधित हुई है। इन स्थानों

को भी चिन्हंकित करने की जरूरत है। निहारिका क्षेत्र के पांश इलाकों में भी इस वर्ष पानी भर गया। सुभाष चौक से पोड़ीबाहर जाने वाले रास्ते में तीन फीट से भी अधिक पानी भर गया था। यहां बच्चे तैरते हुए नजर आए। नालों के जाम होने से इस समस्या के उत्पन्न होने की जानकारी सामने आई। स्थानीय निवासी अजय का कहना है कि आसपास के ड्रेनेज सिस्टम की इतनी क्षमता नहीं है कि अत्यधिक पानी को

बाहर निकाल सके, नए निर्माण हुए हैं, जिससे मार्ग संकरा हो गया है। नालों की चौड़ाई भी कम है। जिससे कि पानी की निकासी नहीं होती। सिर्फ पोड़ीबाहर जाने वाले रास्ता ही नहीं रवि शंकर नगर, महाराणा प्रताप नगर में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया था। जो बरसात रुकते ही पानी को घर से बाहर निकालते हुए नजर आए।अत्यधिक बारिश से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, तो दूसरी ओर नालों की चौड़ाई कम होने के कारण लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया।

गंदगी और दूषित पानी से बिगड़े हालात

धमतरी। धमतरी नगर निगम के तीन वार्डों में दूषित पानी के कारण पीलिया और टाइफाइड ने महामारी का रूप ले लिया है। नया पारा, रिसाई पारा और रामसागर पारा इन तीनों वार्डों में अब तक 37 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मासूम बच्चे चपेट में आए हैं। इन बच्चों की हालत गंभीर है।

धमतरी के नया पारा वार्ड में अकेले 20 से ज्यादा लोग पीलिया और टाइफाइड की चपेट में आ चुके हैं। हर घर में कोई न कोई उल्टी, दस्त और बुखार से तड़प रहा है। लोगों का कहना है कि देखते ही देखते पूरा वार्ड बीमारी की चपेट में आ गया है। वार्ड में फैली गंदगी और प्रशासन की लापरवाही के कारण महामारी फैली है।

वाइवासियों ने बताया कि नया पारा वार्ड में दर्जनों अवैध डेयरियां चल रही हैं। इन डेयरियों का गोबर और गंदा पानी सीधे नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे नालियां जाम हैं और

37 से ज्यादा लोग पीलिया-टाइफाइड से पीड़ित



मिल रहा है और लोग मजबूरी में यही जहरीला पानी पीकर बीमार हो रहे हैं।

सिर्फ नया पारा ही नहीं, रिसाई पारा में 10 और रामसागर पारा में 7 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तीनों वार्डों में दहशत का माहौल है। गंदगी के इस आलम से वार्डवासियों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंख बंद किए बैठे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद वार्ड पार्षद को सामने आकर उग्र आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी

गंदगी सड़क पर फैली हुई है। इसी गंदगी का नतीजा है कि नाली का यही दूषित पानी पाइपलाइन के लीकेज से होते हुए लोगों के घरों में सप्लाई हो रहे पीने के पानी में

साइबर ठगी मास्टरमाइंड नीलू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस को साइबर ठगी के मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले तीन माह से पुलिस को चकमा दे रहे साइबर ठगी के आरोपी नीलू यादव को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कबीरधाम जिले के अलावा मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 4 मई 2026 को एक शिक्षक ने साइबर पुलिस थाना कबीरधाम में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर दबाव बनाते हुए रुपये की मांग की गई। यूपीआई के जरिए राशि ट्रांसफर कराई गई।



शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। 8 मई को इसी तरह की

ठगी के एक अन्य मामले में भी केस दर्ज किया गया।पुलिस ने मोबाइल नंबरों की तकनीकी जानकारी, बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। आरोपी की लोकेशन मध्यप्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़ और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामने आई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था। ठगी की रकम विभिन्न चॉइस सेंटरों के माध्यम से ट्रांसफर

करवाता था। जांच में आरोपी के खिलाफ निवाड़ी जिले में केस दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक मामलों की भी जानकारी जुटा रही है। साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित की ठगी गई रकम को समय रहते होल्ड करया गया है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद राशि पीड़ित को वापस कराई जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें। पुलिस थाना या साइबर पुलिस को सूचना दें, ताकि ठगी की रकम को समय रहते सुरक्षित कराया जा सके

बस्तर से बदलाव शुरू होकर दूसरे संभागों तक पहुंचेगा : बैज

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी 2028 विधानसभा चुनाव और उसके लिए जमीनी स्तर पर अपने ब्लाक अध्यक्षों को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार करने के लिए कांग्रेस संगठन की पाठशाला बस्तर से शुरू हुई। प्रशिक्षण शिविर की शुरुवात पहले चरण में बस्तर से की गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संगठन सुजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी पांचों संभागों में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत बस्तर संभाग से हुई। इन शिविरों में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने क्लास ली। ब्लॉक कांग्रेस और मास्टर ट्रेनर पर



बेहतर चर्चा हुई। यहां से निकलने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष नए कलेवर के रूप में काम करेंगे। आक्रामक, बदले हुए रूप में जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ेंगे। इससे कांग्रेस को फायदा होगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। पीसीसी चीफ ने कहा कि आगामी चुनाव पर पूरा फोकस रखा गया। प्रशिक्षण के समापन के बाद मिशन 2028 की तैयारी भी बस्तर में तेज कर दी जाएगी। ब्लॉक अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर आम जनता के बीच पहुंचकर जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत बनाने पर काम करेंगे।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

आवारा कुते ने 13 लोगों को काटा, तीन की हालत गंभीर

बालोद। जिले के डौंडीलोहारा नगर में आवारा कुते के आतंक से लोगों में दहशत फैल गई है। नगर के अलग-अलग इलाकों में एक आवारा कुते ने 13 लोगों को अपना शिकार बनाया। कुते के हमले में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। किसी के पैर तो किसी के हाथ में कुते ने काटा है। कुछ लोग डौंडीलोहारा के ही हैं तो कुछ लोग बाहर के हैं। जानकारी के मुताबिक, आवारा कुते ने नगर के अलग-अलग स्थानों पर लोगों पर अचानक हमला कर दिया। कुते के काटने से घायल सभी लोगों को तत्काल डौंडीलोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि कुते के हमले में घायल 3 लोगों की हालत गंभीर है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद नगर में लोगों के बीच डर का माहौल है। लोग घरों से निकलने में भी सतर्कता बरत रहे हैं। टिकरापारा निवासी 60 वर्षीय भगवती यादव किराना दुकान में काम करके वापस घर लौट रही थी, जिसे कुते ने निशाना बनाया।

हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के मामलों में एक अहम निर्णय

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता के मामलों में एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि अब पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे की आय और संपत्ति से जुड़े शपथ पत्र पर क्रॉस एक्जामिनेशन करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह निर्णय पारित किया है। इस तरह हाईकोर्ट ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी के आय के जरिए पर सवाल पूछने से रोक दिया गया था। दरअसल रायपुर निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दुर्ग परिवार न्यायालय में अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का आवेदन लगाया है। जिसमें महिला ने अपने आय और संपत्ति का विवरण शपथ पत्र के साथ पेश किया था। जिसपर बहस करते हुए बीते 3 अगस्त को आय और संपत्ति के ब्योरे से संबंधित जिरह को फैमिली कोर्ट ने रोक दिया था, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति ने कहा कि ऐसा करने से वो प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, जो सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है।

दुर्ग में स्वाइन फ्लू का कहर जारी: 4 नए केस मिले

दुर्ग-भिलाई। जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले में चार नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पांच अगस्त से एक सितंबर के बीच स्वाइन फ्लू के कुल 17 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इनमें से 9 मरीज एक्टिव हैं और सभी का उपचार स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एक्टिव मरीजों में सात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दो मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सभी मरीजों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। नए मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी कर रही है। संक्रमित मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ अस्पतालों से मिलने वाली रिपोर्टों पर भी नजर रखी जा रही है। किसी अस्पताल में स्वाइन फ्लू का नया मरीज सामने आने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरबा के जंगल से मां की ममता का अदभुत वीडियो

कोरबा। कोरबा के जंगल से सामने आया हथिनी और उसके नन्हे बच्चे का एक वीडियो मां की ममता की ऐसी तस्वीर दिखा रहा है, जो हर किसी का दिल छू लेगा। कटघोरा वनमंडल के मातौन जिल में कैमरे में कैद हुआ यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वनमंडल में विचरण कर रहे 50 हथियों के झुंड में से एक हथिनी अपने नन्हे बच्चे के साथ नदी की ओर से जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी। रेत वाला रास्ता छोटे बच्चे के लिए चलने में कठिन था। नन्हे पैर रेत में धंस रहे थे। यह देख मां हथिनी ने पहले खुद को हटाकर रास्ता आसान करने का फैसला किया।वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हथिनी अपनी सूंड और पैरों से आगे की रेत को हटाकर समतल कर रही है। वह कुछ दूर तक रेत को हटाकर बच्चे के लिए चलने लायक रास्ता बनाती रही। उसके पीछे-पीछे नन्हा शावक धीरे-धीरे उसी बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मां बार-बार रुककर देखती कि बच्चा आ रहा है या नहीं, फिर आगे रास्ता बनाती।

रायगढ़ में यात्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत कई घायल

रायगढ़। जिले में बुधवार की सुबह यात्री बस और तेज रफ्तार ट्रक में आमने-सामने टक्कर हो गई। इस घटना में जहां 13 यात्री घायल हो गए। जिसमें सात की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना से बस के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले के नारायणपुर से रायगढ़ तक चलने वाली द्विध्वी यात्री बस क्रमांक सीजी 13 बीएल 6425 रोजाना की भांति सुबह यात्रियों को लेकर निकली थी। बताया जा रहा है कि बस जब रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तेजपुर के करनारा घाट के समीप पहुंची ही थी कि सामने की तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक जेएच 09 बीजे 8764 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए यात्री बस को सामने से जोरदार ठोकर मार दिया। अचानक घटी इस घटना के बाद जहां यात्रियों में चीख पुकार मच गई।

42 लीटर के फ्यूल टैंक में भर दिया 48 लीटर पेट्रोल

बिल देखकर कार चालक के उड़े होश, पेट्रोल पंप पर मचा बवाल

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के गुडेली क्षेत्र में स्थित डी.सी पेट्रोल पंप पर कार की टंकी की क्षमता से अधिक पेट्रोल भरने का मामला सामने आने के बाद जमकर विवाद हो गया। बंजारी निवासी अनुपम खूंटे अपनी महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ में पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। पेट्रोल भरने के बाद मशीन की रीडिंग और बिल में दर्ज मात्रा देखकर उन्होंने पंप कर्मचारियों से सवाल किया, जिसके बाद मामला विवाद में बदल गया। अनुपम खूंटे का कहना है कि उनकी महिंद्रा एक्सयूवी 3 एक्सओ की फ्यूल टंकी की क्षमता कंपनी के अनुसार करीब 42 लीटर है। इसके बावजूद पेट्रोल पंप

की मशीन में 48 लीटर से अधिक पेट्रोल डाले जाने की रीडिंग दिखाई गई। बिल में भी कार की बताई गई क्षमता से करीब 7 लीटर अधिक पेट्रोल दर्ज था। यही अंतर देखकर ग्राहक ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी और आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई।

विवाद बढ़ने पर पेट्रोल पंप परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही। विवाद बढ़ता देख डायल 112 को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पेट्रोल पंप पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद ग्राहक और पेट्रोल पंप प्रबंधन, दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं, पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना है कि पंप पर लगी मशीनें निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रही हैं। प्रबंधन ने किसी भी तरह की मशीन संबंधी गड़बड़ी से इनकार किया है। ऐसे में वास्तविक स्थिति क्या है, यह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मामले में अनुपम खूंटे ने पुलिस से

शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि पेट्रोल पंप की मशीन की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार की टंकी की क्षमता और मशीन में दर्ज पेट्रोल की मात्रा में इतना अंतर कैसे आया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पेट्रोल पंप की मशीनों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। लोगों ने नापतौल विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जिले में नापतौल विभाग के अधिकारी नहीं होने के कारण पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब जांच और तकनीकी परीक्षण के बाद ही यह साफ होगा कि मशीन में दर्ज पेट्रोल की मात्रा में अंतर का कारण क्या था।

जांजगीर में अनूठा प्रदर्शन, चंदा मांग कर जिला अस्पताल को दिया

जांजगीर। एक बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। जिला अस्पताल के सामने टेंट लगा कर चंदा मांगा गया। इस प्रदर्शन को बंद कराने पहुंचे जिला प्रशासन को ढाई घंटे में इकट्ठा किए गए 5 हजार 925 रुपये दिए गए और जिला अस्पताल में बर्न यूनिट खोलने की मांग की गई। जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध करने की मांग को लेकर समाज सेवी कोसमंदा निवासी कृष्णा टंडन के साथ स्थानीय लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए जनसहयोग अभियान चलाया। उन्होंने जिला अस्पताल के सामने टेंट लगा कर एक दान पात्र रखा और लोगों से सहयोग की अपील की। लोगों ने बताया कि जांजगीर जिले में लंबे समय से बर्न यूनिट की जरूरत महसूस की जा रही है। बच्ची की मौत के बाद यह मांग और भी गंभीर हो गई है। अभियान के दौरान लोगों से मिले सहयोग से 5,925 रुपये की राशि एकत्रित की गई। जांजगीर जिला अस्पताल के सामने अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और

जिला प्रशासन से तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुस्साए लोगों से चर्चा की और उनकी मांगों को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन लिया। तहसीलदार ने नागरिकों की ओर से उठाई गई बर्न यूनिट की मांग को जायज बताया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मांग और अस्पताल से संबंधित अन्य शिकायतों को शासन के संज्ञान में लाया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की सुविधा शुरू करने की दिशा में पहल हो। जांजगीर जिला अस्पताल की अब राज्य शासन में मेडिकल कॉलेज के रूप अपग्रेड कर दिया है। इसके बाद भी जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की व्यवस्था नहीं है।

विरासत, विकास और विश्वास

की नई यात्रा में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां

अतीत की अमूल्य धरोहर से भविष्य के विकसित छत्तीसगढ़ तक

“छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी गौरवशाली विरासत, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता से है। हमारी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। कांगेर वैली को वैश्विक पहचान दिलाने से लेकर मल्हार, सिरपुर और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तक, हम अपनी जड़ों को सहेजते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी विरासत पर गर्व करें और विकास के नए अवसरों से भी जुड़ें।

— विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़”

छत्तीसगढ़ आज केवल प्राकृतिक संसाधनों और जनजातीय संस्कृति की भूमि भर नहीं है, बल्कि यह अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत, तेज़ी से विकसित होती अधोसंरचना और जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार एक ओर जहां अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर विकास और जनविश्वास के नए आयाम भी स्थापित कर रही है। राज्य की यह यात्रा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ने की एक ऐसी विकासगाथा है, जिसमें विरासत, विकास और विश्वास तीनों समान रूप से शामिल हैं।

विरासत का वैभव

हजारों वर्षों के इतिहास को संजोता छत्तीसगढ़

शैलचित्रों की धरती

सिंहनपुर, कबरा पहाड़ (रायगढ़), चितवाडोंगरी (बालोद) और चरामा (कांकेर) के प्रागैतिहासिक शैलचित्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। चरामा में मिले लगभग 10,000 वर्ष पुराने चित्र विश्वभर के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

सिरपुर की प्राचीन सभ्यता

महानदी के तट पर स्थित सिरपुर 5वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहां 12 बौद्ध विहार, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, मठ, मूर्तियां और भूमिगत स्नानगृह के अवशेष मिले हैं।

ताला की रूद्रशिव प्रतिमा

बिलासपुर जिले के ताला स्थित देवरानी-जेठानी मंदिर परिसर से प्राप्त रूद्रशिव प्रतिमा युसकालीन कला का अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें अनेक जीव-जंतुओं के स्वरूप शिव की विराट कल्पना को दर्शाते हैं।

मल्हार के ताम्रपत्र

बिलासपुर के मल्हार में मिले लगभग 1400-1500 वर्ष पुराने ताम्र-पट्टिकाएं भारतीय इतिहास के लिए अमूल्य धरोहर हैं। इन पर अंकित ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में शासन, संस्कृति और सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

अन्य पुरातात्विक स्थलों की पहचान

दीपादीह (सरगुजा), पचराही (कबीरधाम), करकाभाट (बालोद) और तरीघाट (दुर्ग) जैसी जगहें महापाशाणकाल से मध्यकालीन इतिहास तक की धरोहरों को संजोए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें

- सिंहनपुर और कबरा पहाड़ (रायगढ़)
- चितवाडोंगरी (बालोद)
- चरामा (कांकेर)
- सिरपुर (महासमुंद)
- ताला - देवरानी-जेठानी मंदिर (बिलासपुर)
- दीपादीह (सरगुजा)
- पचराही (कबीरधाम)
- करकाभाट (बालोद)
- तरीघाट (दुर्ग)

अनूठी जैव-विविधता प्रदेश की अद्वितीय पहचान

वैश्विक पहचान की दहलीज पर



यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल कांगेर वैली

बस्तर स्थित कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची (Tentative List) में शामिल किया गया है। कोटमसर, कैलाश और दंडक गुणाएं, दुर्लभ वन्यजीव, 900 से अधिक वनस्पति प्रजातियां, 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां और अनूठी जैव-विविधता इसे विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाती हैं। यह उपलब्धि पर्यटन, स्थानीय रोजगार और जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के नए अवसर पैदा करेगी।

लोक संस्कृति और परंपराएं

हमारी पहचान, हमारी आत्मा

- 35 से अधिक जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति
- पंडवानी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, करमा, दीवारी जैसे लोकनृत्य
- बस्तर कला, ढोकरा शिल्प, बॉस और लकड़ी की कला का संरक्षण
- ग्रामीण और इको-टूरिज्म के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक अवसरों से जोड़ना



विकास के नए आयाम

आधुनिक छत्तीसगढ़ की पहचान

नई विधानसभा - नए संकल्प

नवा रायपुर में बना अत्याधुनिक विधानसभा भवन लोकतंत्र, पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा का गौरवपूर्ण अध्याय बताया।

शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास

राज्य में IIT, IIM और AIIMS जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) में उत्कृष्ट प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले 'फ्रंट रनर' श्रेणी में शामिल होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहे हैं।

जनजातीय उत्थान की मजबूत पहल

प्रधानमंत्री जनमन अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में पक्का आवास, बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।

खेल प्रतिभाओं को मिल रही पहचान

जशपुर के युवा धावक अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में 10.15 सेकंड का रिकॉर्ड बनाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी जगह निति की प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में उनका उल्लेख प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख उपलब्धियां

- कांगेर वैली को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल।
- नई और अत्याधुनिक विधानसभा भवन।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में अग्रणी जिले।
- IIT, IIM और AIIMS जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं।
- प्रधानमंत्री जनमन अभियान।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।
- खेल, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान।

राज्यपाल डेका ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का किया आत्मीय स्वागत



रायपुर। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्यपाल रमेन डेका, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन,



सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रयाम बिहारी जायसवाल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में उनका आत्मीय स्वागत किया।



उपराष्ट्रपति का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा, राज्य सभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने आत्मीय स्वागत की। इसी प्रकार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक



पुनंद मिश्रा, अनुज शर्मा, सुनील सोनी, मोती लाल साहू और जनप्रतिनिधि अशोक बजाज और मुख्य सचिव विकासशील, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में आत्मीय स्वागत किया।

सीजीपीएससी घोटाला: ईडी का बड़ा खुलासा प्रश्नपत्र के बदले वसूले गए करोड़ों रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 1 सितंबर 2026 को रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान डिजिटल उपकरण, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई।

ईडी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जांच रायपुर में दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में तत्कालीन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों पर वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचा था प्रश्नपत्र जांच में ईडी को पता चला कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र आरोपियों के रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा



अभ्यर्थियों तक निजी बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाए गए। इसके बदले अवैध रूप से रकम लिए जाने और उप जिलाधिकारी तथा उप पुलिस अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चयन कराने का आरोप है।

3 करोड़ से अधिक की वसूली
ईडी के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने वर्ष 2021 की लोक सेवा आयोग परीक्षा का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद रकम वसूली। जांच में तीन करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय का पता चलने का दावा किया गया है। इसमें से करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को दिए जाने की बात सामने आई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम और प्रभाव के इस्तेमाल का आरोप जांच एजेंसी के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर ने नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रभावित करने और उनसे रकम वसूलने के लिए

तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक केके चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक विशेष कर्तव्य अधिकारी के प्रभाव का भी इस्तेमाल किए जाने की बात जांच में सामने आई है।

उत्कर्ष चंद्राकर गिरफ्तार

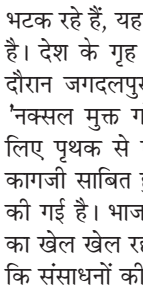
ईडी ने इससे पहले 3 जून 2026 को भी इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था। जांच के दौरान दर्ज बयानों, मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर ईडी ने दावा किया कि उत्कर्ष चंद्राकर अपराध से अर्जित आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था। इसी आधार पर उसे 1 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

1 सितंबर को ईडी ने दुर्ग में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक केके चंद्रवंशी, धमतरी और बलरामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तत्कालीन विशेष कर्तव्य अधिकारी चेतन बोहरिया से जुड़े ठिकानों तथा सिकोल भांटा, दुर्ग में सेवानिवृत्त पटवारी कमलेश राजपूत के निवास सहित पांच ठिकानों पर दबिश दी।

भाजपा का बस्तर मॉडल विकास का नहीं, आदिवासियों के विनाश और कॉर्पोरेट लूट का मॉडल है : दीपक बैज

रायपुर। भाजपा द्वारा प्रचारित बस्तर के कथित विकास मॉडल को स्थानीय बस्तरिया आदिवासियों के विनाश और कॉर्पोरेट लूट का मॉडल बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि डबल इंजन सरकार बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 'विकास और सुरक्षा' के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और सरेंडर कर चुके सर्पित नक्सली पुनर्वास नीति के लाभों से वंचित हैं।

कल ही महाराष्ट्र के गढ़ चिरीली से मुख्यधारा में लौटे 50 से अधिक पूर्व नक्सलियों को उनके गृह क्षेत्र बस्तर भेजा गया, पुनर्वास योजनाओं के वायदों का कितना लाभ उन्हें प्रदान किया गया यह बताने की स्थिति में सरकार नहीं है। पीड़ित और प्रभावित दर दर भटक रहे हैं, यह सरकार केवल उनके जूखों की नुमाइश कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 के बस्तर पंडुम के दौरान जगलपुर के सार्वजनिक मंच से घोषणा किया था कि 'नक्सल मुक्त गाँव' घोषित प्रत्येक गाँव को विकास कार्यों के लिए पुष्क से एक-एक करोड़ रुपये दिया जाएगा, वह सिर्फ कागजी साबित हुआ है। किसी भी गाँव को यह राशि जारी नहीं की गई है। भाजपा सरकार बस्तर के नाम पर केवल झूठे प्रचार का खेल खेल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि संसाधनों की लूट का विरोध करने वाले निर्दोष आदिवासियों पर नक्सली सहयोगी होने का ठप्पा लगाकर उन्हें जेलों में दूँसा गया है, आज जब दुर्दांत नक्सलियों को माफ़ी मिल गई फिर उन हजारों आदिवासियों की रिहाई क्यों नहीं हो रही है जिन पर सहयोगी होने का आरोप है? सुरक्षा के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और बस्तर के जल-जंगल-जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करके कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अमीर-गरीब के बीच असमानता खाई की तरह बढ़ रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 'विश्वास, विकास और सुरक्षा' की नीति पर काम करते हुए निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए जस्टिस पटनायक समिति बनाई थी।



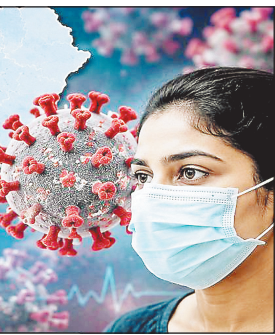
भटक रहे हैं, यह सरकार केवल उनके जूखों की नुमाइश कर रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 के बस्तर पंडुम के दौरान जगलपुर के सार्वजनिक मंच से घोषणा किया था कि 'नक्सल मुक्त गाँव' घोषित प्रत्येक गाँव को विकास कार्यों के लिए पुष्क से एक-एक करोड़ रुपये दिया जाएगा, वह सिर्फ कागजी साबित हुआ है। किसी भी गाँव को यह राशि जारी नहीं की गई है। भाजपा सरकार बस्तर के नाम पर केवल झूठे प्रचार का खेल खेल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि संसाधनों की लूट का विरोध करने वाले निर्दोष आदिवासियों पर नक्सली सहयोगी होने का ठप्पा लगाकर उन्हें जेलों में दूँसा गया है, आज जब दुर्दांत नक्सलियों को माफ़ी मिल गई फिर उन हजारों आदिवासियों की रिहाई क्यों नहीं हो रही है जिन पर सहयोगी होने का आरोप है? सुरक्षा के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और बस्तर के जल-जंगल-जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करके कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे अमीर-गरीब के बीच असमानता खाई की तरह बढ़ रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 'विश्वास, विकास और सुरक्षा' की नीति पर काम करते हुए निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए जस्टिस पटनायक समिति बनाई थी।

कोरोना की दस्तक, दो जिलों में मिले मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की दस्तक हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के दो जिलों रायपुर और राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। स्वाइन फ्लू के बीच कोरोना के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इतिहास जानकारी के अनुसार, रायपुर में मिले कोरोना संक्रमित मरीज का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है, जबकि राजनांदगांव में चिन्हित मरीज का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोनों मामलों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। मरीजों के परिजनों के संपर्क भी जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतने और



तत्काल जांच कराने की अपील की है। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने, बीमारी के लक्षण होने पर जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 37 मरीज सक्रिय

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू यानी संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1 जनवरी 2026 से 1 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश

में अब तक 158 11ह1 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 37 मरीज फिलहाल एक्टिव केस हैं। जिलेवार आंकड़ों में रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अब तक 66 11ह1 मामले सामने आए हैं, जिनमें 8 मरीज अभी एक्टिव हैं। वहीं दुर्ग में 17 मामले दर्ज हुए हैं और यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 एक्टिव केस हैं।

रायपुर के बाद बिलासपुर में 20, दुर्ग में 17, रायगढ़ में 10, धमतरी और कोरबा में 9-9, राजनांदगांव में 4, जबकि बस्तर और बेमेतरा में 3-3 11ह1 मामले सामने आए हैं। जांजगीर-चांपा, कांकेर, सूरजपुर और सरगुजा में 2-2 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बालोद, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, जशपुर, महासमुंद, एमसीबी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और सकरी में 1-1 मामला सामने आया है।

आंकड़ों के अनुसार बलरामपुर, बीजापुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव, कोरिया, मुंगेली, नारायणपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सुकमा में इस अवधि में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

विवेक गर्ग को मिली एफएडीए स्टेट चेयरमैन की जिम्मेदारी

रायपुर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंसकी 62वाँ एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) का आयोजन होटल ले मेरिडियन, नई दिल्ली में किया गया। जिसमें स्वस्तिक सेल्स एंटरप्राइजेज के संचालक विवेक गर्ग को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (एफएडीए) का स्टेट चेयरमैन निर्वाचित किया गया, जिस पर रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। राडा ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री गर्ग अपने अनुभव, नेतृत्व क्षमता एवं सक्रिय कार्यशैली के माध्यम से प्रदेश के ऑटोमोबाइल डीलर्स के हितों को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। श्री विवेक गर्ग को ऑटोमोबाइल व्यवसाय का 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे पूर्व में रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके कार्यकाल में एसोसिएशन के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गईं। जिनमें राडा ऑटो एक्सपो 2023 का सफल आयोजन प्रमुख रहा। उन्होंने ऑटोमोबाइल व्यवसायियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष उठाया तथा उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए।



भाजपा के कुशासन में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर: शुक्ला

रायपुर। गाँव-गाँव में डायरिया-मलेरिया के तांडव और शहरों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खोफ के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से जमीन पर स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। बस्तर से लेकर रायपुर तक मलेरिया, डायरिया और



टीबी से बेकसूर ग्रामीणों की जान जा रही है, और अब स्वाइन फ्लू ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भाजपा सरकार केवल कागजी समीक्षा बैठकों और विज्ञापनों में व्यस्त है। अस्पतालों में न डॉक्टर हैं, न दवाइयाँ और न ही जांच की सुविधा। साथ सरकार की इस नाकामी और आपराधिक लापरवाही के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि स्वास्थ्य बजट का सही क्रियान्वयन न होने, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, समय पर दवाओं की आपूर्ति न होने और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के बजट में कटौती के चलते ही स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। शहरी और मैदानी इलाकों में स्वाइन फ्लू (11ह1) ने भयावह रूप ले लिया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड और जरूरी दवाओं का भारी अभाव है।

स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिजली बिल: उत्तम जायसवाल

रायपुर। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल, बढ़ी हुई टैरिफ दरों और बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इसके पहले मंत्रिमंडल ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ निकाल कर



शेयर बेचने का फैसला किया था। पहले बिजली की कीमते बढ़ाया, स्मार्ट मीटर लगाकर लूटा, 400 यूनिट छूट खत्म किया। अब बिजली कंपनी ही बेच रही है। एक ओर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं के कई गुना बढ़े बिजली बिलों की शिकायतें सामने आ रही हैं, दूसरी ओर सरकार ने 1 जुलाई से बिजली की दरों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जब जनता महंगे बिजली बिलों से परेशान है, तब सरकार को उपभोक्ताओं को राहत देने की चिंता होनी चाहिए, लेकिन इसके उलट बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है। प्रश्नचिह्न में टाटा पावर द्वारा रायपुर, धरसीवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसीलों के लिए वितरण लाइसेंस का आवेदन इसका गंभीर संकेत है।

महाराष्ट्र मंडल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 6 को

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की आध्यात्मिक समिति रविवार, 6 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर सुंदर और आनंदमयी भजन संध्या के साथ नर्तन मुने बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस और मनोरंजक खेल का आयोजन किया गया है। मंडल की स्वास्थ्य, योग और आध्यात्मिक प्रभावी आस्था अभय काले ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में जहां एक



आराध्य की भक्ति होगी। वहीं दूसरी ओर बालकृष्ण और राधा की वेषभूषा पहने बच्चे कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र होंगे। राधा-कृष्ण वेषभूषा में तीन माह से पांच वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकेंगे। रविवार शाम छह बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में पांच से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मटकी फोड़ और अन्य मनोरंजक खेलों का आयोजन किया जाएगा। आस्था के अनुसार आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी और राधा-कृष्ण वेषभूषा और मटकी फोड़ में अपने बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए आध्यात्मिक समिति की महिला प्रमुख सृष्टि दंडवते और पुरुष प्रमुख आलोक शेंडे से संपर्क किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बच्चों के मनोरंजन के लिए है। सृष्टि ने जोर देकर कहा कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसमें प्रतिभागी बच्चों को आकर्षक पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सामान गुम करने पर इंडिगो को 1.82 लाख का हर्जाना

रायपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग रायपुर ने एक यात्री का सामान गुम करने के मामले में फैसला सुनाया है। इंटरलोक एंक्विजिशन लिमिटेड (इंडिगो) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी करार देते हुए 1,82,000 रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। समता कॉलोनी, रायपुर निवासी 28 वर्षीय आशुतोष जाखोदिया ने यह परिवाद दायर किया था। मामले के अनुसार, परिवारी का विवाह 4 दिसंबर 2015 को आगरा में हुआ था। विवाह में शामिल होने के बाद वे 5 दिसंबर 2015 को दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट से लौट रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो स्टाफ ने समय की कमी और ससाहंत की भीड़ का हवाला देते हुए उनसे अनुरोध न किया कि वे अपना सामान (तीन बैग) फ्लाइट में न ले जाएं तथा आश्वासन दिया कि बैगले दिन यह सामान रायपुर पहुंचा दिया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर इंडिगो के कर्मचारियों ने पहले बताया कि उनके तीनों बैग उसी फ्लाइट में लोड हो गए हैं और लगेज बेल्ट से एकत्र किए जा सकते हैं, लेकिन बेल्ट पर पहुंचने पर परिवारी को तीन बैग नहीं मिले। उन्हें क्लिप क्रमांक 632881 व 632804 दिए गए। बार-बार पृच्छाछ के बावजूद इंडिगो ने 18 दिसंबर 2015 को स्वीकार किया कि सामान गुम हो गया है।



छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

ग्रामीणों की आपत्ति पर मंत्री ओपी चौधरी ने लिया फैसला

पिरदा की जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगी सरकार

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के लिए चिन्हांकित पिरदा गांव की जमीन का अब सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद धरसीवा विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।

बैठक में ग्रामीणों ने प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना था कि चिन्हांकित जमीन पर वे लंबे समय से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 20 प्रतिशत लोगों के मकान भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में जमीन



अधिग्रहण होने से उनके सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

ग्रामसभा में भी जताई थी आपत्ति

पिरदा में आरडीए द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए

जमीन चिन्हांकित किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों और किसानों में चिंता बढ़ गई थी। ग्रामीणों ने ग्रामसभा में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने की मांग की थी।

विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया मुद्दा

ग्रामीणों की मांग को धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से

लेते हुए वित्त एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी को ग्रामीणों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार को विधायक अनुज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की।

आरडीए को पिरदा की जमीन नहीं लेने के निर्देश

मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कहा कि यदि ग्रामीण अपनी जमीन पर आवासीय प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं, तो उनकी इच्छा के खिलाफ वहां परियोजना नहीं लाई जाएगी। मंत्री ओपी चौधरी ने आरडीए को पिरदा की जमीन नहीं लेने के निर्देश देने की बात कही। सरकार के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की बात कही है।

दिसंबर तक होगी शिक्षकों की पदस्थापना: शिक्षामंत्री यादव

रायपुर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय किलेपाल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने छात्राओं को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगातें दी हैं। विद्यालय में खेल सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देते हुए मंत्री ने परिसर में आधुनिक बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण कराने तथा खेल सामग्री तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही छात्राओं द्वारा विषय शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर तक होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया में इस



विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी, ताकि बच्चों के पढ़ाई प्रभावित न हो।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्राओं से सीधा और आत्मीय संवाद किया। जब बालिकाओं ने अपनी खेलकूद की रुचि साझा की, तो मंत्री ने खेल अधोसंरचना को तुरंत विकसित करने की बात कही और साथ ही सभी छात्राओं को कंपास बॉक्स

सहित जरूरी शैक्षणिक सामग्री तुरंत वितरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरकार दूरस्थ अंचलों में भी खेल और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री ने स्कूल व छात्रावास स्टाफ के साथ बैठक कर दिनचर्या में व्यापक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुबह उठने के बाद छात्राओं को मैदान में दौड़, पीटी और नियमित योग करवाया जाए।